मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं नई दिल्ली से एक साथ प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र

हमारा उद्देश्य सेवा समर्पण जनकल्याण

एक सत बुलेटिन

E-mail: eksatbulletin@gmail.com | ग्वालियर, शनिवार 17 अक्टूबर 2026 | वर्ष-08, अंक-186, पृष्ठ-08, मूल्य- दो रुपए | Website: www.eksatbulletin.in

औद्योगिक विकास को गति देने तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

दीपावली से पहले आयोजित होगा चंबल संभाग स्तरीय औद्योगिक सम्मेलन

एक सत बुलेटिन, भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य शासन प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार के लिए शासन की ओर से हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि दीपावली से पहले चंबल संभाग स्तरीय औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इससे क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को विस्तार देने और नए उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री ऐदल सिंह कंसाना, मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल तथा सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. सुदाम खाड़े सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।



मुख्यमंत्री डॉ. यादव जनविश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित उद्यम संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से संवाद कर क्षेत्र में औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार सृजन, निर्यात तथा उद्योगों के विस्तार से जुड़े विषयों पर चर्चा की। संवाद में लगभग 20 उद्यमियों ने सहभागिता की और शासन से प्राप्त सहयोग, उपलब्ध सुविधाओं तथा विभिन्न विभागों के साथ समन्वय के संबंध में अपने अनुभव साझा किए।

राज्य सरकार ओबीसी हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आज शुक्रवार को प्रातः ओबीसी महासभा के प्रतिनिधि मंडलों ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ओबीसी हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। न्याय संगत और तार्किक व्यवस्था के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से ओबीसी आरक्षण के विषय पर सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई और ओबीसी के सभी संगठनों से वार्ता कर मजबूती के साथ उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा गया था। राज्य सरकार इस विषय को टालने की दृष्टि से नहीं अपितु उसका समुचित हल निकालने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर राज्य सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का बिंदुवार अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख राज्य सरकार की ओर से मजबूती से अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में औद्योगिक विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना तथा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। उन्होंने चंबल एक्सप्रेस-वे के आसपास नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की संभावनाओं पर भी उद्यमियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मैसर्स एजीआई ग्रीन पैक की ग्लास विनिर्माण इकाई की सराहना करते हुए कहा कि ग्लास उद्योग को प्रोत्साहित कर प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की दिशा में प्रभावी पहल की जा सकती है।

हवाई किराये पर लगाम लगाने वाले नियमों को मंजूरी

एजेन्सी, नई दिल्ली



हवाई सफर करने वाले यात्रियों को टिकटों की बढ़ती कीमतों और अतिरिक्त शुल्क से राहत मिलने की उम्मीद के बीच केंद्र सरकार ने विमानन क्षेत्र से जुड़े नए नियमों को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत बनाए गए नियमों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इन्हें दो सप्ताह के भीतर प्रकाशित किए जाने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से प्रकाशित नियम अगली सुनवाई पर पेश करने को कहा है। यह मामला हवाई किराये में अचानक बढ़ोतरी, यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा और विमानन कंपनियों की मनमानी पर नियंत्रण की मांग से जुड़ा है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रशासनिक मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके बाद पीठ ने सरकार को अगली सुनवाई पर नियम पेश करने का निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। सामाजिक कार्यकर्ता एस लक्ष्मीनारायणन ने याचिका दायर कर विमानन क्षेत्र के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र नियामक बनाने की मांग की है, जो किराये में पारदर्शिता सुनिश्चित करे और यात्रियों के हितों की रक्षा करे।

केंद्र ने पहचान सत्यापन के लिए जारी किए नए नियम

अगर आधार नहीं तो भी नहीं रुकेगा सरकारी लाभ

एजेन्सी, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों की पहचान सत्यापित करने और आधार से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से 14 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना में बताया गया है कि आधार उपलब्ध नहीं होने पर नामांकन के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें पहचान की जांच करने, बायोमेट्रिक सत्यापन में नाकामी की स्थिति से निपटने और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं के



फायदे से वंचित होने से बचाने के प्रावधान शामिल हैं। इसका उद्देश्य पहचान सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान वास्तविक लाभार्थियों के हितों की रक्षा करना है।

भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक, ये नियम उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार आधारित पहचान सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। अधिसूचना में आधार संख्या उपलब्ध नहीं होने पर नामांकन के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, पहचान की पुष्टि करने और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में समस्या आने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। इन प्रावधानों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी परेशानी या आधार उपलब्ध नहीं होने के कारण पात्र व्यक्ति सरकारी सहायता से वंचित न रह जाएं।

12 मिनट तक पूरे जापान में अफरातफरी रही

रूस में 7 तीव्रता का भूकंप जापान में 9.9 का अलर्ट



एजेन्सी, नई दिल्ली

रूस के कामचटका प्रायद्वीप में शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे 7 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। इसके कुछ देर बाद जापान की मौसम एजेंसी ने गलती से 9.9 तीव्रता के भूकंप की चेतावनी जारी कर दी। इससे देशभर में अफरातफरी मच गई। हालांकि, एजेंसी ने करीब 12 मिनट बाद अलर्ट वापस ले लिया। जापान की मौसम एजेंसी ने इस गलती के लिए माफी मांगी है।

भूकंप अलर्ट में इतनी बड़ी गलती कैसे हुई?

जापान की भूकंप चेतावनी प्रणाली जमीन पर लगे सेंसर से मिले शुरूआती आंकड़ों के आधार पर भूकंप की तीव्रता और उसके असर का अनुमान लगाती है। यह काम कुछ ही समय में किया जाता है। शुरूआत में आंकड़े अधूरे होने के कारण अनुमान गलत हो सकता है। लेकिन इस बार 9.9 तीव्रता का अलर्ट जारी करना बड़ी चूक थी। इतनी तीव्रता का भूकंप अब तक दर्ज नहीं किया गया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता का जरूरत से ज्यादा अनुमान लगाने के कारण गलत चेतावनी जारी हुई थी। एजेंसी अब इसकी वजह की जांच कर रही है। शुरूआती आंकड़े अधूरे होने, भूकंप का निगरानी केंद्रों से दूर आने या आसपास एक साथ कई भूकंप आने से अनुमान प्रभावित हो सकता है।

इस महीने संसद का स्पेशल सेशन बुला सकती है सरकार

लोकसभा सीटें बढ़ाने और परिसीमन बिल पेश करने का अनुमान

एजेन्सी, नई दिल्ली

केंद्र सरकार इसी महीने संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। इसमें लोकसभा सीटें बढ़ाने के लिए संविधान (131वां संशोधन) बिल, परिसीमन (संशोधन) बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल को पास कराया जाएगा। इनके जरिए महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। 6 महीने (16 और 17 अप्रैल) पहले सरकार पहले प्रयास में कामयाब नहीं रही थी और लोकसभा में दो तिहाई बहुमत जुटा नहीं पाई थी। अब कहा जा रहा है कि सरकार ने संख्याबल जुटा लिया है।

विशेष सत्र बुलाने से करीब एक हफ्ते पहले इसकी सूचना दी जा सकती है। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को खत्म हुआ था, लेकिन इसका अब तक सत्रावसान नहीं किया गया है।



लोकसभा में 20, राज्यसभा में 9 सांसदों की जरूरत

लोकसभा में 543 सांसद हैं। 3 सीटें खाली हैं। इनमें से ठऊअ के 318 सांसद हैं। बिल को पास कराने के लिए दो-तिहाई यानी 360 वोट चाहिए। अगर डीएमके के 22 सांसद बिल का समर्थन करते हैं तो बिल के समर्थन में 340 सांसद हो जाएंगे। यानी इसके बाद भी भाजपा को लगभग 20 सांसदों की जरूरत है। राज्यसभा में 245 सीटें हैं। 3 खाली हैं। इस तरह 240 में से NDA के 153 सांसद हैं। यहां बिल को पास कराने के लिए 162 सांसद चाहिए। यानी, यहां भी NDA को छोटी पार्टियों के 9 सांसदों की जरूरत पड़ेगी।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परिसीमन बिल पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव संसद में रखने से पहले सभी दलों से चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में खड़गे ने चेतावनी दी कि सरकार को व्यापक संविधान संशोधन बिल को फिर जबरन पास कराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसी कोशिश पहले भी नाकाम रही है। खड़गे ने मानसून सत्र समापन नहीं होने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 64 दिन बाद भी लोकसभा और राज्यसभा का सत्रावसान नहीं हुआ है।

एफएसएसएआई

बिगबास्केट, फ्लिपकार्ट, जेमिनी एडिबल्स को भ्रामक दावों पर नोटिस

एजेन्सी, नई दिल्ली



खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने भ्रामक स्वास्थ्य दावों के लिए बड़ी कार्रवाई की है। उसने हैदराबाद स्थित जेमिनी एडिबल्स एंड फैट्स इंडिया लिमिटेड, बिगबास्केट और फ्लिपकार्ट को नोटिस जारी किए हैं। यह नोटिस राइस ब्रान तेल की बिक्री से जुड़े गलत विज्ञापनों को लेकर दिए गए हैं।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी। नोटिस 'फ्रीडम कुकिंग राइस ब्रान ऑयल' उत्पाद के भ्रामक दावों के संबंध में जारी हुए हैं। इस उत्पाद का प्रचार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर किया जा रहा था। दावों में 'खराब कोलेस्ट्रॉल कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनाए रखता/बढ़ाता है' शामिल था। साथ ही, '10,000+ पीपीएम नेचुरल ओरिजानोल' का दावा भी किया गया था। नियामक ने पाया कि कोलेस्ट्रॉल और हृदय-स्वास्थ्य संबंधी ये दावे विज्ञापन और दावा विनियम, 2018 के तहत अनुमत नहीं थे। जेमिनी एडिबल्स एंड फैट्स इंडिया अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से खाद्य उत्पाद बेच रही थी। कंपनी के पास ई-कॉमर्स गतिविधि के लिए वैध केंद्रीय लाइसेंस भी नहीं था।

प्रशासन ने पहले रोक लगाई फिर छूट दी

बांग्लादेश में छात्रों ने मंदिर के सामने गोमांस पकाया

एजेन्सी, ढाका

बांग्लादेश की जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में 12 अक्टूबर को मंदिर के पास गोमांस पकाने को लेकर विवाद हो गया। इसके दो दिन बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कैंपस में पशु काटने से बचने का नोटिस जारी किया। इसके विरोध में मुस्लिम छात्रों के एक समूह ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर को गाय काटकर दावत करने का ऐलान कर दिया। विवाद बढ़ने पर प्रशासन ने दूसरा नोटिस जारी कर कहा कि छात्रों को ऐसे आयोजन करने का अधिकार है, लेकिन इससे दूसरों की धार्मिक गतिविधियों में बाधा नहीं आनी चाहिए।

इस्लामिक कल्चर विभाग के छात्रों ने रखा था कार्यक्रम

12 अक्टूबर को जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर विभाग के 17वें बैच के छात्रों ने कैंपस में गोमांस की खिचड़ी बनाने का कार्यक्रम रखा। यह जगह यूनिवर्सिटी के केंद्रीय मंदिर के पास थी। मंदिर समिति के सदस्य सचिव जॉय साहा ने इइउ बांग्ला को बताया कि गोमांस की खिचड़ी बनते देख कुछ हिंदू छात्रों ने विरोध किया। मामला बढ़ने पर यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद आयोजकों ने मंदिर से कुछ दूरी पर जाकर खाना बनाया। आयोजकों ने कहा कि उनका किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। उन्होंने चूल्हा बनाने में इस्तेमाल हुईं मंदिर के पास रखी ईंटें वापस रख दीं और खाना बनाने के लिए कैंटीन से लोहे का चूल्हा मंगाया। साहा के मुताबिक, मंदिर समिति को ईंटों से ज्यादा आपत्ति मंदिर के इतने करीब खाना बनाने पर थी। उसी रात सनातनी छात्रों ने कैंपस में मार्च निकाला। इसके बाद सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ गया।

14 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कैंपस में पशु वध से बचने के लिए नोटिस जारी किया। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, साफ-सफाई और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का हवाला दिया गया था।



नोटिस में ढाका साउथ सिटी कॉर्पोरेशन के नियमों का भी जिक्र था। बांग्लादेश के पशु वध और मांस गुणवत्ता नियंत्रण कानून, 2011 के तहत तय बूचड़खानों के बाहर पशु काटने पर कानूनी पाबंदियां हैं। नियम तोड़ने पर जेल या जुमार्ना हो सकता है। यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर डॉ. एमडी आजम खान ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि प्रशासन को कैंपस में पशु काटने की योजना की जानकारी मिली थी। दुर्गा पूजा के दौरान किसी नए विवाद से बचने के लिए छात्रों से ऐसा नहीं करने की अपील की गई थी।

नोटिस के विरोध में छात्रों ने दावत का ऐलान किया

प्रशासन के फैसले से नाराज छात्रों के एक समूह ने शुक्रवार को गाय काटकर दावत करने की घोषणा की। आयोजन समिति के एक सदस्य ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बीबीसी बांग्ला को बताया कि छात्र पहले दुर्गा पूजा के बाद कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन नोटिस जारी होने के बाद उन्होंने इसे शुक्रवार को ही करने का फैसला किया। आयोजकों के मुताबिक, कार्यक्रम के लिए चंदा इकट्ठा करके एक गाय खरीदी गई है। सोशल मीडिया पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 70 टका रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई। आयोजकों ने बताया कि गाय काटने का कार्यक्रम मंदिर के सामने करने के बजाय आर्ट्स बिल्डिंग के पास खुले मैदान में किया जा सकता है।

दूसरे नोटिस में आयोजन की छूट दी

छात्रों के विरोध के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दूसरा नोटिस जारी कर अपनी स्थिति साफ की। इसमें कहा गया कि 12 अक्टूबर को खिचड़ी बनाने को लेकर हुआ विवाद प्रॉक्टर के हस्तक्षेप से उसी दिन सुलझा लियागया था। अगले दिन संबंधित पक्षों के बीच बातचीत से भी मामला निपट गया था। प्रशासन ने कहा कि पशु वध से बचने की अपील का मकसद धार्मिक तनाव बढ़ने से रोकना था। हालांकि, इससे गलतफहमी पैदा हुई, जिसके लिए उसने खेद जताया। दूसरे नोटिस में स्पष्ट किया गया कि छात्रों को कैंपस में पशु वध समेत कार्यक्रम आयोजित करने का अधिकार है, लेकिन किसी आयोजन से दूसरे लोगों की धार्मिक गतिविधियों में बाधा नहीं आनी चाहिए।

उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य महत्वपूर्ण पदों के नतीजे

शशांक शेखर हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर ने अध्यक्ष पद पर एकतरफा और शानदार जीत दर्ज की है। इस हाई-प्रोफाइल चुनावी मुकाबले में शशांक शेखर को कुल 304 से अधिक मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी विजय पांडे को महज 145 से अधिक वोटों से ही संतोष करना पड़ा। वहीं, संगठन के महत्वपूर्ण सचिव पद पर सौरभ सुंदर ने बाजी मारते हुए जीत हासिल की है। मुख्य चुनाव अधिकारी राकेश पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि हालांकि चुनाव परिणामों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अंतिम घोषणा जल्द ही एक औपचारिक कार्यक्रम के माध्यम से की जाएगी।अध्यक्ष और सचिव पद के अलावा एसोसिएशन की कार्यकारिणी के अन्य प्रमुख पदों पर भी प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। उपाध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में नवीन दुबे ने जीत हासिल की, जबकि सह-सचिव पद पर अनुज अग्रवाल विजयी घोषित हुए। इसी क्रम में कोषाध्यक्ष पद पर दिवेश जैन ने सफलता प्राप्त की और पुस्तकालय सचिव के पद पर गुलाब कली पटेल ने बाजी मारी। चुनाव परिणाम घोषित होते ही बार एसोसिएशन परिसर में जश्न का माहौल बन गया। एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता संजय अग्रवाल, स्थाई समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा और पूर्व सचिव निखिल तिवारी समेत कई वरिष्ठ वकीलों ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का पुष्पहार पहनाकर गर्मजोशी से आत्मीय स्वागत किया। दे देर रात तक चली गहन और लंबी मतगणना के बावजूद कार्यकारिणी सदस्य पद के परिणामों की घोषणा को फिलहाल रोक दिया गया है। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, इस पद के लिए शुक्रवार को दोबारा मतगणना कराई जाएगी, जिसके बाद ही अंतिम नतीजे सार्वजनिक किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए अधिवक्ता आशीष मिश्रा, गोपेश तिवारी, माधवी चतुर्वेदी, रूचिका गोहिल, सना खान और सिद्धार्थ श्रीवास्तव चुनावी मैदान में हैं और अपनी जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं। सहायक चुनाव अधिकारी रियाज मोहम्मद और राजेन्द्र जायसवाल ने चुनावी प्रक्रिया का ब्यौरा देते हुए बताया कि गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक पूर्ण शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक माहौल में मतदान कराया गया था। बार एसोसिएशन के कुल 500 पंजीकृत मतदाता अधिवक्ताओं में से 460 अधिवक्ताओं ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का उपयोग किया।

पोस्टर में की गई अपील पर मुस्लिम दुकानदारों की कड़ी आपत्ति

जबलपुर के खेरमाई मेले में पोस्टर से मचा विवाद गैर हिंदू दुकानदारों से सामान न लेने की अपील

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थित प्रसिद्ध बड़ी खेरमाई मंदिर परिसर में आयोजित मेले में लगे कुछ नए पोस्टरों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विश्व हिंदू महासंघ द्वारा मंदिर परिसर और मेले में लगाए गए इन विवादित पोस्टरों के माध्यम से हिंदू श्रद्धालुओं से यह अपील की गई है कि वे किसी भी गैर-हिंदू विक्रेता या दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान न खरीदें। मेले में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं के बीच ये पोस्टर आकर्षण और तीखी चर्चा का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। संगठन की ओर से लगाए गए इन होर्डिंग्स और पोस्टरों में हिंदू समाज के लोगों से अपनी खरीदारी को लेकर विशेष दिशा-निर्देश और अपील जारी की गई है। संगठन इसे अपना वैचारिक संदेश बताकर प्रचारित कर रहा है। हालांकि, दूसरी तरफ मेले के भीतर अपनी दुकानें सजाकर व्यापार कर रहे मुस्लिम समुदाय के दुकानदारों और व्यापारियों ने इस तरह के संदेशों और पोस्टरों पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। व्यापारियों का कहना है कि पारंपरिक मेलों और आयोजनों में हमेशा से सभी समुदायों और धर्मों के लोग आपसी भाईचारे के साथ मिलकर अपना कारोबार करते आए हैं। ऐसे में किसी एक समुदाय विशेष को लक्षित करके यह अपील करना कि उनकी दुकानों से सामान न खरीदा जाए, न केवल अनुचित है बल्कि यह आपसी सौहार्द को भी ठेस पहुंचाता है। खेरमाई मेले में गरमाया मुद्दा, स्थानीय लोगों में चर्चा इन पोस्टरों के सामने आने और उस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आने के बाद खेरमाई मेले का यह पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय नागरिकों और प्रबुद्धजनों का कहना है कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों और मेलों में हर वर्ग के हजारों श्रद्धालु आस्था के साथ पहुंचते हैं। इस प्रकार के विवादास्पद संदेशों और बैनर-पोस्टरों से मेले का शांत माहौल और सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। प्रशासन की भूमिका और आगे की स्थिति पर नजर फिलहाल इन पोस्टरों के लगाए जाने और बढ़ते विवाद के बावजूद जिला प्रशासन या पुलिस की ओर से किसी प्रकार की आधिकारिक कार्रवाई या औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। मेले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर दोनों पक्षों की तीखी प्रतिक्रियाओं और अब प्रशासनिक रुख पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

प्राकृतिक खेती, नवाचारों ने डिंडौरी, सीधी, उमरिया और टीकमगढ़ जिले को दिलाया राष्ट्रीय सम्मान?

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में शामिल मप्र के डिंडौरी, उमरिया, सीधी और टीकमगढ़ ने देशभर में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। इन जिलों में प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण और भंडारण संबंधित कार्यों को सराहते हुए सोमवार को दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इन जिलों में कृषि के विविध क्षेत्रों में किए गए नवाचारों ने अन्य क्षेत्रों के किसानों को नई राह दिखाई दी है। अनूपपुर, शहडोल सहित आठ जिलों के दल को आमंत्रित किया था, लेकिन उन्हें स्थान नहीं मिला। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत डिंडौरी को 'फसल विविधीकरण एवं सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने' श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के मार्गदर्शन में विभागों के समन्वय से जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया। एक वर्ष में 873 नए परिवारों व 12,258 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया। किसानों के लिए 33 जैव संसाधन केंद्र स्थापित किए व 4,650 किसानों का जैविक प्रमाणीकरण कराया गया। मिट्टी की उर्वरता, जल संरक्षण को ध्यान में रख रामतिल, मसूर, सरसों जैसी कम पानी वाली फसलों पर फोकस रखा गया है फसल विविधिकरण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और विभागों के बीच समन्वय के आधार पर जिले ने यह उपलब्धि हासिल की है।

हादसे में मरने वाले युवक की पहचान अभी नहीं हो पाई

जबलपुर के भेड़ाघाट स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आया युवक, हाथ-पैर कटने से मौत

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



जबलपुर के भेड़ाघाट रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की सुबह एक दर्दनाक और सनसनीखेज हादसा सामने आया है, जहां मालगाड़ी की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। यह दुर्घटना प्लेटफार्म नंबर-1 के नजदीक मेन लाइन नंबर-2 पर हुई, जिसमें ट्रेन की चपेट में आने से उस व्यक्ति के दोनों हाथ और बायां पैर बुरी तरह कट गए। मौके पर पहुंचे रेलवे डॉक्टर ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 10:35 बजे प्रधान आरपीएफ आरक्षक कुलदीप सिंह ने सहायक उपनिरीक्षक धीरज कुमार को इस दुर्घटना की सूचना दी। बताया गया कि ट्रेन के पहिए के नीचे व्यक्ति का शरीर फंसा हुआ है। सूचना मिलते ही हरकत में आए रेलवे प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। परिचालन विभाग ने सूझबूझ दिखाते हुए मालगाड़ी को हल्का पीछे करवाया, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों और आरपीएफ के जवानों की संयुक्त मदद से व्यक्ति को बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंचे रेलवे डॉक्टर शुभ आशीष ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस दुखद घटना की जानकारी मिलते ही जीआरपी जबलपुर के सहायक उपनिरीक्षक भागचंद उइके और प्रधान आरक्षक कौशल तिवारी अपने दल-बल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि, फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस उसकी पहचान सुनिश्चित करने के प्रयासों में जुटी है। इस अप्रत्याशित हादसे के कारण भेड़ाघाट बीसीएन ट्रेन सुबह 10:35 बजे से 10:57 बजे तक कुल 22 मिनट विलंबित रही।

जबलपुर के प्राइवेट अस्पतालों में फायर सेफ्टी को लेकर लापरवाही

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



शैल्बी हास्पिटल में आग की घटना के बाद एक बार फिर शहर के अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए है। फायर सेफ्टी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि जिले में 179 से पंजीकृत निजी अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, जिनमें से 30 से 40 प्रतिशत के पास वैध फायर एनओसी नहीं है या उनकी एनओसी एक्सपायर हो चुकी है। हर हादसे के बाद जांच, नोटिस और सीलिंग की कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ महीनों में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। यही कारण है कि आग लगने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं।स्वास्थ्य विभाग और निगम आमने-सामने मध्य प्रदेश अग्निशमन व आपातकालीन सेवा सामान्य नियम-2026 लागू होने के बाद अब हर साल 30 जून तक फायर ऑडिट, फायर सुपरवाइजर की नियुक्ति, फायर टैक्स और बिना एनओसी पर 5 लाख जुर्माना व सीलिंग का प्रावधान है। लेकिन हकीकत यह है कि सरकारी अस्पताल खुद इन नियमों का पालन नहीं कर रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक फायर सेफ्टी को पंजीयन नवीनीकरण से सीधे नहीं जोड़ा जाएगा, माक ड्रिल हर महीने अनिवार्य नहीं होगी और सरकारी अस्पतालों की इलेक्ट्रिक लोड ऑडिट कर पुरानी वायरिंग नहीं बदली जाएगी, तब तक जबलपुर में अस्पताल आग के ढेर पर ही बैठे रहेंगे। अगली बड़ी घटना से पहले सिस्टम जाग जाए, यही सबसे बड़ी जरूरत है।

लेन-देन के विवाद में मारपीट और धमकी, जबलपुर पुलिस ने दर्ज की तीन एफआईआर

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



साइबर ठगी के मामलों के अलावा शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में शराब पीने या अन्य कारणों से रुपये मांगने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायतों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है। कोतवाली थाना क्षेत्र में छोटी देवन के पास दीक्षितपुरा निवासी 55 वर्षीय रश्मि वाजपेयी ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके बेटे दुर्गेश वाजपेयी ने 14 अक्टूबर की रात शराब के नशे में घर पहुंचकर उनसे 10 लाख रुपये मांगे। महिला के अनुसार, जून 2026 में जमीन बिकने के बाद बेटे ने व्यवसाय करने के लिए 30 लाख रुपये लिए थे, लेकिन उसने उन पैसों का क्या किया, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। रश्मि वाजपेयी ने अपनी दोनों बेटियों की शादी का हवाला देते हुए रुपये देने से मना किया तो आरोपी ने गाली-गलौज कर रसोई में रखा सामान तोड़ना शुरू कर दिया। बीच-बचाव करने आई बेटी प्रिया के चेहरे पर मुक्का मार दिया, जिससे उसके होंठ में चोट आई। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने धारा 115(2), 119(1), 296(बी) और 351(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। गौरीघाट थाना क्षेत्र में बादशाह हलवाई मंदिर, गली नंबर तीन निवासी 33 वर्षीय साहिल चौधरी ने शिकायत की कि वह प्लंबर का काम करता है। 14 अक्टूबर की रात करीब आठ बजे वह अपने घर के पास खड़ा था, तभी विकास नायक वहां पहुंचा और शराब पीने के लिए रुपये मांगने लगा। साहिल द्वारा रुपये देने से मना करने पर आरोपी ने पास में रखी ईंट उठाकर उसके सिर पर हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।

फ्लाईओवर पर मदनमहल रोटरी के समीप हादसा, आरोपी चालक वाहन सहित फरार

तेज भागते हाईवा की टक्कर से स्कूटर सवार की मौत

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। दमोहनाका-मदनमहल फ्लाईओवर पर मदन महल रोटरी के पास तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने एक स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में स्कूटर सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके दो अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी हाईवा चालक वाहन समेत मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, लटकारी के पड़ाव निवासी शरद उर्फ बड्डू बर्मन ने गढ़ा थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने पुलिस को बताया कि वह निजी काम करता है। शुक्रवार को तड़के करीब साढ़े तीन बजे वह अपने दोस्त अंकित झारिया और अमन केशरवानी के साथ अमन की एक्टिवा पर सवार होकर अमन की बुआ के घर देवताल जा रहा था। वाहन अमन चला रहा था, जबकि शरद और अंकित पीछे बैठे हुए थे। जब वे मदनमहल फ्लाईओवर पर रोटरी पार कर रहे थे, तभी सामने से तेज गति और लापरवाही से आ रहे रेत लदे हाईवा के चालक ने उनकी एक्टिवा में टक्कर मार दी। एक की मौत और दो घायल, परिजनों ने किया चक्काजा इस टक्कर से तीनों दोस्त एक्टिवा समेत सड़क पर जा गिरे। हादसे में शरद के सिर और अंकित के बाएं हाथ में गंभीर चोटें आई, जबकि अमन के सिर में गहरी चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया और मृतक अमन के शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया। मृतक की बहन काजल अग्रवाल ने बताया कि अमन गोल बाजार में चाट-फुलकी का ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने थाने के सामने जमा होकर जोरदार प्रदर्शन और चक्काजाम कर दिया। परिजनों ने फरार हाईवा चालक को जल्द गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है।

बुजुर्ग महिला को साइबर ठगों ने बनाया निशाना

साइबर ठगी के पांच मामले दर्ज, बुजुर्ग महिला से 7.52 लाख रुपये की धोखाधड़ी

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पांच मामलों में लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी कर लाखों रुपये की राशि हड़पने की शिकायतें सामने आई हैं। इनमें गोरखपुर थाना क्षेत्र की 69 वर्षीय महिला से एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दिलाने का झांसा देकर 7 लाख 52 हजार रुपये ठगने का मामला भी शामिल है। इसके अलावा घमापुर, खितौला, बेलखेड़ा और केंट थाना क्षेत्रों में भी धोखाधड़ी की शिकायतों पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है। गोरखपुर थाना क्षेत्र में गायत्री भवन, कृपाल चौक गुप्तेश्वर निवासी 69 वर्षीय प्रवेश धीर की फेसबुक प्रोफाइल पर अभिनेता विजय थलपति से संबंधित आर्थिक सहायता एवं ऋण उपलब्ध कराने का लिंक आया था। महिला ने लिंक पर क्लिक किया, जिसके बाद अज्ञात मोबाइल नंबरों से कॉल आने लगे। फोन करने वालों ने अभिनेता से संबंधित योजना के नाम पर एक करोड़ रुपये दिलाने का झांसा दिया और प्रक्रिया पूरी करने के लिए छोटी-छोटी रकम जमा कराने को कहा। आरोपियों द्वारा भेजे गए यूपीआई आईडी और स्कैनर के माध्यम से महिला ने 6 सितंबर से 9 अक्टूबर 2026 के बीच अलग-अलग व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के नाम पर कुल 7 लाख 52 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बावजूद उसे कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। आरोपियों ने अंतिम बातचीत में गोल्ड लेकर आने और रास्ते में पुलिस द्वारा पकड़े जाने की कहानी सुनाई। इसके बाद छह लाख रुपये और देने का दबाव बनाया तथा पैसे नहीं देने पर पुलिस द्वारा पकड़वाने और घर सील कराने की धमकी दी। महिला ने घटना की जानकारी नागपुर से जबलपुर आए अपने बेटे वरुण धीर को दी। शिकायत पर गोरखपुर पुलिस ने धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घमापुर थाना क्षेत्र में दीपक डेयरी के पीछे कांचघर निवासी 28 वर्षीय ज्योति टेकाम ने शिकायत दर्ज कराई कि 21 सितंबर 2026 को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। उसने स्वयं को एक्सिस बैंक का कर्मचारी बताते हुए खाते में रिवॉर्ड पॉइंट होने और उन्हें रिडीम कराने की बात कही। आरोपी ने लिंक भेजकर उसे गूगल पर टाइप करने के लिए कहा। निर्देशों का पालन करने के बाद उनका मोबाइल नंबर कॉल फॉरवर्डिंग में चला गया। इसी दौरान उनके क्रेडिट कार्ड से 1 लाख 24 हजार 118 रुपये कटने का ओटीपी संदेश आया। उन्होंने ओटीपी किसी से साझा नहीं किया और तत्काल एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क कर कार्ड ब्लॉक करा दिया। शिकायत के अनुसार, अज्ञात व्यक्ति ने धोखाधड़ी कर उनके क्रेडिट कार्ड से राशि ट्रांसफर कर ली। पुलिस ने धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। खितौला थाना क्षेत्र में गढ़ा क्षेत्र के देवताल पहाड़ी, रामायण मंदिर के पीछे निवासी 48 वर्षीय राधा बाई अहिरवार ने शिकायत की कि उनके केनरा बैंक खाते से उनकी जानकारी और अनुमति के बिना 89 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए गए। उनका बेटा राकेश अहिरवार सब्जी का ठेला लगाता है और मां के बैंक खाते से अपने मोबाइल पर गूगल पे का इस्तेमाल करता है। शिकायत के मुताबिक, 10 अक्टूबर को मोबाइल अपने आप अपडेट होने लगा और बंद हो गया।

न्यूज ब्रीफ

ग्वालियर में शुभ मुहूर्त में जमकर हो रही खरीदारी

ग्वालियर। पितृपक्ष में खरीदारी से परहेज करने वाले लोग अब नवरात्र में शुभ मुहूर्त संग बाजारों का रुख कर रहे हैं। इसका असर शहर के कारोबार पर दिखाई देने लगा है। मकान, आभूषण, वाहन और इलेक्ट्रानिक्स सामान की खरीदारी में लगभग 30 से 35 प्रतिशत की बढ़त नजर आ रही है।नवरात्र में नई वस्तुओं की खरीदारी को शुभ मानने की परंपरा के चलते ग्राहक अपनी जरूरतों के साथ लंबे समय से टाली जा रही खरीदारी भी पूरी कर रहे हैं। रियल एस्टेट में संपत्ति की बुकिंग, सराफा बाजार में आभूषणों की खरीदारी, आटोमोबाइल शोरूम में वाहनों की बिक्री और इलेक्ट्रानिक्स दुकानों पर घरेलू उपकरणों की मांग बढ़ रही है। बाजार में आई इस तेजी का असर कारोबारियों के चेहरों पर भी नजर आने लगा है।

ग्वालियर-चंबल में अगले तीन दिन गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट

ग्वालियर। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में गुरुवार को मौसम में अचानक बदलाव आया। सुबह से लेकर दोपहर बाद चार बजे तक खासी गर्मी थी और तापमान दिन का तापमान 34.7 डिसे रहा। लेकिन चार बजे के बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला और आसमान पर बादल छाने के साथ तेज ठंडी हवा चलने लगी। हवा की गति 20 किमी प्रतिघंटा रही। इससे पूरा वातावरण ठंडा हो गया। चूंकि दिन की गर्मी की वजह से लोग हल्के कपड़े पहने हुए थे। ऐसे में लोगों को ठंड का एहसास हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ चक्रवातीय प्रसार के असर से हुआ है। आगामी तीन दिन में अंचल में तेज हवा के साथ मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है।

दीपावली से पहले बिगड़ा रसोई का बजट, 65 रु किलो तक पहुंची चीनी

ग्वालियर। त्योहारों की तैयारी के बीच शक्कर की बढ़ती कीमतों ने आम परिवारों का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। नवरात्र से दीपावली तक घरों में मिठाइयां, पकवान और प्रसाद बनाने की परंपरा है, लेकिन इस बार इनकी मिठास जेब पर भारी पड़ सकती है।शक्कर के दाम तीन दिन में करीब 500-600 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गए हैं। थोक भाव 5100 से 5200 रुपये से बढ़कर 5600 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। फुटकर बाजार में शक्कर 60 से 65 रुपये प्रति किलो बिक रही है।

बीमा कंपनी के कर्मचारी ने की आत्महत्या, गेमिंग में लाखों हारा

ग्वालियर। शहर के सिटी सेंटर इलाके में आनलाइन गेमिंग की लत का एक और खौफनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक बीमा कंपनी में कार्यरत 30 वर्षीय युवक ने आनलाइन गेम में लगातार लाखों रुपये हारने और बढ़ते कर्ज से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने पटेल नगर स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आनलाइन जुए और गेमिंग का दलदल युवाओं को किस हद तक मानसिक तनाव और बर्बादी की ओर धकेल रहा है।

घाटमपुर में अतिक्रमण की शिकायत पर राजस्व विभाग ने की जांच

ग्वालियर। ग्राम घाटमपुर में भूमि पर प्लॉटिंग कर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत पर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देशानुसार राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में सर्वे नंबर 24 की भूमि पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण तथा सर्वे नंबर 158 की भूमि पर बाउंड्रीवॉल कर अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलेक्टर को 14 अक्टूबर 2026 को ग्राम घाटमपुर के सर्वे नंबर 20, 21, 24, 158, 162, 163, 164, 165, 180, 170, 171 और 172 पर प्लॉटिंग कर अतिक्रमण किए जाने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। कलेक्टर ने शिकायत की मौके पर जांच करने के निर्देश एसडीएम लश्कर श्री नरेंद्र बाबू यादव को दिए थे। निर्देशों के पालन में 15 अक्टूबर 2026 को एसडीएम लश्कर नरेंद्र बाबू यादव, तहसीलदार गोशपुरा श्रीमती वंदना यादव एवं राजस्व अमले ने मौके पर पहुंचकर जांच की।इसी प्रकार, सर्वे नंबर 158, जिसका रकबा 0.209 है, के संपूर्ण भाग पर मोहिते गार्डन की संचालक नंदिता दास द्वारा बाउंड्रीवॉल बनाकर भूमि को घेरने और अतिक्रमण किए जाने की बात जांच में सामने आई।

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का सप्तम दीक्षांत समारोह

उपाधियां राष्ट्र सेवा का संकल्प भी हैं: राज्यपाल पटेल

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर।



राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा दीक्षांत समारोह हर विद्यार्थी के जीवन में अत्यंत गौरव, सम्मान और आत्म-विश्वास का क्षण होता है। दीक्षांत समारोह में कला एवं संगीत की शिक्षा के लिये मिली उपाधि हर विद्यार्थी के लिए प्रतिभा का प्रमाण तो है ही, साथ ही यह कला और संगीत से समाज एवं राष्ट्र सेवा का संकल्प भी है। राज्यपाल श्री पटेल बुधवार को ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के सप्तम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि आप सब भारत की गौरवशाली संस्कृति, कला व संगीत को विश्व पटल पर नई ऊँचाईयों तक ले जाने का संकल्प लें। साथ ही भारत को वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र और विश्व गुरू बनाने में योगदान दें। उन्होंने यह भी कहा कि विद्यार्थी अपने मन में सदैव यह भाव रखें कि शिक्षा तभी शोभायमान होती है, जब उसमें संस्कृति की संवेदना हो। राज्यपाल श्री पटेल ने स्वर्ण पदक व उपाधि प्राप्त सभी विद्यार्थियों एवं उनके गुरूजनों व माता-पिता को बधाई एवं शुभकामनाऐं भी दीं। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का गरिमामयी सप्तम दीक्षांत समारोह शुक्रवार को राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार में राज्यपाल मंगुभाई पटेल की अध्यक्ष्यता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तानसेन सम्मान से अलंकृत प्रख्यात शास्त्रीय गायक पं. अजय पोहनकर (पुणे), विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्कृति शिक्षा उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी एवं प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिकन्यास व धर्मस्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र सिंह लोधी, विश्वविद्यालय की कुलगुरू प्रो. स्मिता सहस्त्रबुद्धे एवं कार्यपरिषद के सदस्यगण मंचासीन थे।दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024-25 और 2025-26, दो वर्षों के कुल 67 स्वर्ण व 368 उपाधियां प्रदान की गईं। इसके अलावा अलग-अलग संकायों की कुल 14 शोध उपाधियां भी प्रदान की गई। कार्यकम के दौरान विश्वविद्यालय की दीक्षांत स्मारिका 2026 का विमोचन भी मंच से किया गया। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कला, संस्कृति समाज व राष्ट्र की नींव को मजबूत करती है। कला व संस्कृति की तरक्की के बिना किसी भी राष्ट्र का विकास अधूरा होता है। इसलिये नई पीढ़ी संगीत और कला के क्षेत्र में शोध, नवाचार और अनुसंधान के लिये आगे आए। उन्होंने कहा तकनीकी प्रगति के साथ-साथ विलुप्त हो रहे लोक संगीत और कलाओं के संरक्षण व संवर्धन के लिये चिंतन जरूरी है। युवा शक्ति की कला साधना, सतत प्रयास और योगदान से ही भारत का वास्तविक सांस्कृतिक उत्थान होगा।

राज्यपाल श्री पटेल ने कार्यक्रम में मौजूद गुरूजनों और छात्र-छात्राओं का आह्वान किया कि वे अपने ज्ञान और गुणों से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत गरीब, वंचित और प्रतिभावान बच्चों के उत्थान में सहयोग करें। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने संगीत सम्राट तानसेन व बैजू बावरा जैसे महान संगीतज्ञों की साधना स्थली एवं कलापोषक व संगीत संरक्षक राजा मानसिंह तोमर व गालव ऋषि की तपोभूमि ग्वालियर को प्रणाम कर अपने उदबोधन की शुरूआत की। साथ ही कहा भारतीय शास्त्रीय संगीत मनोरंजन मात्र का साधन नहीं, यह धर्म और अध्यात्म से जुड़कर व्यक्ति के तन-मन और आत्मा को निर्मल करता है।शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव श्री अतुल कोठारी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में शिक्षा की गुरूकुल परंपरा रही है। जिसमें परिवार का भाव होता है। हमारी संस्कृति में शिक्षा ग्रहण करने के तीन सोपान बताए गए हैं, जिनमें श्रवण, मनन व शिक्षा को जीवन में धारण करने की बात शामिल है। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे अपने भीतर सीखने की भावना सदैव जागृत रखें।

अन्य मुख्य बिंदु

समारोह के में स्व. पं. पीएल गोहदकर की ओर से गायन में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र आयुष मिश्र, अक्षत मिश्रा को पं. राजा भैया पूछवाले संगीत परिषद स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया गया।

समारोह में प्रो रिमिता सहस्त्रबुद्धे की ओर से समस्त संकाय में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र पुनीत कदवाने को स्व. प. पीएल गोहदकर स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया गया।

विवि के कार्यपरिषद सदस्य चंद्रप्रताप सिकरवार की ओर से नाट्य एवं रंगमंच में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र अमिताभ आचार्य व विकास सिंह गोयल को स्व.श्रीमती शारदा महेंद्र सिंह स्मृति स्वर्ण प्रदान किया गया।

विवि के विद्या परिषद सदस्य अशोक आनंद की ओर से समर्पित समाजसेवी लाल रामशरण आनंद स्मृति स्वर्ण पदक नाट्य एवं रंगमंच में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र रजत सिंह व ऐश्वर्य दुबे को प्रदान किया गया।

प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैलों का उपयोग करने के लिए रासेयो माधव महाविद्यालय ने चलाया जागरूकता अभियान

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



प्लास्टिक हटाओं प्रकृति बचाओं के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों ने उसका विकल्प मानते हुये कपड़े के थैलों का वितरण किया। प्लास्टिक हमारी प्रकृति को एक भयावक राक्षस के रूप में नष्ट कर रही है जिसके लिये हमें जागरूक होना आवश्यक है। माधव महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाई द्वारा जागरूकता कार्य किया गया। माधव महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाई द्वारा महाविद्यालय में नवरात्र के दिनों में हम प्लास्टिक की जगह कपड़े थैलों का उपयोग करेंगें। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉ. संजय कुमार पाण्डेय राष्ट्रीय सेवा योजना एवं डॉ सरिता दीक्षित कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में किया गया। डॉ. पाण्डेय ने बताया कि प्लास्टिक का उपयोग हमारे मानव समाज के लिये नुकसान दायक है। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करके मानव उसको खाद्य पदार्थ सहित फैंक देता है। इस खाद्य पदार्थ के कारण जानवर प्लास्टिक को ही खा जाते हैं जो उनके जीवन के लिए काफी नुकसान दायक है। जानवरों के जीवन को बचाना भी मनुष्य का कर्तव्य है। डॉ. दीक्षित ने बताया कि आजाद भारत यदि मनुष्य की देन सिंगल यूज प्लास्टिक से भी आजादी प्राप्त कर लेता है तो इससे सुखद आजादी का महाउत्सव नहीं हो सकता यह सिंगल यूज प्लास्टिक मानव के साथ में जीव-जन्तु व पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। आस-पास के फैले हुये कचडे को यदि हम नष्ट करते हैं तो इस समय के मौसम में होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। इस कार्यक्रम में डॉ कौशलेन्द्र अवस्थी डॉ प्रशांत साहू, डॉ. दीपक शिन्दे डॉ दीप्ति नारंग, डॉ. संजय गुप्ता, डॉ. रूपाली गोखले, विष्णु दिलीप चौहान एवं स्वयंसेवक में कृष्णा रजक मोहम्मद अकरम कचन कुशवाह रिमझिम शाक्य, तनु जाटव वैष्णवी बिहारी, आशीष कुशवाह, चेतन सविता दिशात प्रजापति आदि लोग उपस्थित थे।

मास्टरमाइंड रियाल चौधरी देता था बांग्लादेशियों को नई पहचान

ग्वालियर फर्जी पासपोर्ट कांड में भंते से 96 घंटे पूछताछ में खुला राज

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट तैयार करवाने और अवैध रूप से घुसपैठ कराने के बहुचर्चित नेटवर्क मामले में गिरफ्तार किए गए भंते गुलाब राय गौतम से पुलिस और जांच एजेंसियों की पूछताछ का दौर आखिरकार संपन्न हो गया है। स्पेशल टास्क फोर्स (स्क्वॉड) की तीन अलग-अलग टीमों ने आरोपी भंते से लगातार 96 घंटे तक कड़ाई से पूछताछ की। जांच प्रक्रिया के दौरान एसटीएफ की टीमों ने आरोपी भंते गुलाब राय को इस प्रकरण के अन्य प्रमुख आरोपियों–रियाल चौधरी, नसीम अख्तर और प्रियान चौधरी के सामने बैठाकर पूछताछ की। लंबी पूछताछ और आमने-सामने कराई गई तफ्तीश में इस गिरोह के संचालन को लेकर कई चौंकाने वाले और महत्वपूर्ण राज सामने आए हैं। 96 घंटे चली लगातार पूछताछ और गहन छानबीन के बाद सामने आए तथ्यों के अनुसार, इस पूरे फर्जी पासपोर्ट और अवैध घुसपैठ रैकेट का मुख्य सरगना रियाल चौधरी है। जांच एजेंसियां अब इस रैकेट के नेटवर्क, अन्य संभावित सहयोगियों और आर्थिक लेन-देन के स्रोतों को पूरी तरह खंगालने में जुटी हुई हैं, ताकि मामले से जुड़े अन्य चेहरों को भी बेनकाब किया जा सके । घुसपैठ कराने के बहुचर्चित मामले में गिरफ्तार किए गए भंते गुलाब राय गौतम से पूछताछ का दौर आखिरकार पूरा हो गया है। एसटीएफ की तीन अलग-अलग टीमों ने भंते से लगातार 96 घंटे तक पूछताछ की।

ग्वालियर हाईकोर्ट से बर्खास्त निगम कर्मचारी को राहत बहाली की जगह मिलेगा 1.75 लाख रुपये का मुआवजा

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगर निगम में सेवा समाप्ति से जुड़े एक लंबे कानूनी मामले में राहत देते हुए मनोज सिंह राणा के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने उनकी मुआवजे की राशि में बढ़ोतरी करते हुए इसे डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर 1.75 लाख रुपये कर दिया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह मुआवजा राशि नौकरी में पुनः बहाली के विकल्प के तौर पर प्रदान की जाएगी। अदालत में सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता मनोज सिंह राणा की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने दलील दी कि जिस प्रकार से उनकी सेवा समाप्त की गई थी और उसके बाद उन्हें अपने वैध अधिकारों के लिए वर्षों तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी है, उसे देखते हुए निचला मुआवजा पर्याप्त नहीं है। अधिवक्ता ने मुआवजे की राशि में पांच लाख रुपये की अतिरिक्त वृद्धि करने की पुरजोर मांग की थी। इसके साथ ही याचिका में नौकरी में बहाली और संपूर्ण पिछली अवधि के वेतन (बैक वेजेज) का विकल्प भी अदालत के समक्ष रखा गया था। मामले में दोनों पक्षों की दलीलों और परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार करने के बाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के और न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र यादव की युगलपीठ ने मुआवजे की राशि में 25 हजार रुपये की अतिरिक्त वृद्धि करना उचित ठहराया। इस संशोधन के बाद अब अपीलकर्ता को मिलने वाली कुल मुआवजा राशि बढ़कर 1.75 लाख रुपये हो गई है।

रेल यात्रियों के लिए अलर्ट! 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक सिर्फ आगरा कैंट से चलेगी झांसी-दिल्ली एक्सप्रेस

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी और अहम खबर सामने आई है। जाजऊ और भांडई स्टेशनों के बीच स्थित पुल संख्या 1331/1 पर स्टील गर्डर बदलने का कार्य किया जाना है, जिसके चलते उत्तर मध्य रेलवे द्वारा यातायात और बिजली का ब्लॉक लिया गया है। इस तकनीकी कार्य के कारण झांसी-नई दिल्ली एक्सप्रेस का संचालन 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा। रेलवे द्वारा इस अवधि के दौरान ट्रेनों के रूट और संचालन में बदलाव किया गया है। आगरा कैंट स्टेशन से ही संचालित होंगी दोनों ट्रेनें रेलवे प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस निर्धारित अवधि में ट्रेन संख्या 12279 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-नई दिल्ली एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 12280 नई दिल्ली-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस अपने तय मार्ग के बजाय केवल आगरा कैंट स्टेशन से ही संचालित की जाएंगी। यह दोनों ट्रेनें प्रतिदिन नियमित रूप से चलती हैं, और इस तीन दिवसीय ब्लॉक के दौरान इनकी कुल तीन-तीन यात्राएं प्रभावित होंगी। ट्रेनें झांसी और नई दिल्ली के बीच आवागमन करने के बजाय बीच के रूट पर रोक दी जाएंगी। ट्रेन के संचालन में किए गए इस बदलाव के कारण झांसी, ग्वालियर और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने संबंधित यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों की स्थिति की पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

स्कूली वाहनों में नियमों की अनदेखी

बच्चों की सुरक्षा ताक पर, ग्वालियर में धड़ल्ले से चल रहे ओवरलोड स्कूली वाहन

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ताक पर रखकर वाहनों के संचालन का खतरनाक सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर की सड़कों पर दौड़ने वाले ऑटो-रिक्शा, मैजिक और अन्य स्कूली वाहनों में क्षमता से कहीं अधिक बच्चों को भूसे की तरह भरकर ले जाने की मनमानी बेलगाम जारी है। यह गंभीर लापरवाही मासूमों की जान के लिए हर पल एक बड़ा खतरा बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और शिक्षा विभाग जैसे जिम्मेदार महकमों की सुस्त कार्यशैली और लचर निगरानी के कारण जमीन पर कोई ठोस असर नजर नहीं आ रहा है। स्थिति यह है कि सुबह स्कूल जाते समय और छुट्टी के वक्त घर लौटते समय मासूम बच्चे सुरक्षा के तमाम बुनियादी मानकों की धज्जियां उड़ते हुए सफर करने को विवश हैं। बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वाला यह ओवरलोडिंग का गंभीर मामला कई बार अदालतों की देहरी तक भी पहुंच चुका है। इस बाबत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा पूर्व में कड़े निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अदालती आदेशों को भी कागजी खानापूर्ति मानकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अदालत ने अपने ऐतिहासिक आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए थे कि किसी भी स्कूली वाहन में उसकी निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को नहीं बैठाया जाएगा। इसके अलावा, ऑटो और छोटे वाहनों में क्षमता बढ़ाने के लिए अवैध रूप से अतिरिक्त लकड़ी या लोहे की पट्टियां (फट्टियां) लगाकर सीटे बढ़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का हुक्म दिया गया था। अदालत ने यह भी सख्त निर्देश दिए थे कि जो भी वाहन चालक इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उसके ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाएं। इन तमाम दिशा-निर्देशों का एकमात्र और मुख्य उद्देश्य मासूम स्कूली बच्चों की दैनिक यात्रा को सुरक्षित और जोखिममुक्त बनाना था, ताकि किसी भी अप्रिय दुर्घटना को समय रहते टाला जा सके। शहर के विभिन्न इलाकों में सुबह और दोपहर के समय स्कूली वाहनों की छतों, पायदानों और ड्राइवरों की सीटों के आसपास लटके हुए बच्चों को आसानी से देखा जा सकता है। कई बार तो एक छोटे से ऑटो-रिक्शा में तय सीमा से दोगुने से भी अधिक बच्चों को ठूंस-ठूंस कर भर दिया जाता है, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ने का खतरा हमेशा बना रहता है।

संपादकीय

पत्रकारिता की मयार्दा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

पत्रकारिता का उद्देश्य किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल का गुणगान करना नहीं बल्कि जनहित के सवालों को निष्पक्षता, निर्भीकता और जिम्मेदारी के साथ उठाना है। डिजिटल दौर में पत्रकार, स्वतंत्र कंटेंट निमार्ता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बीच अंतर तथा उनकी जवाबदेही पर बहस जरूरी हो गई है।लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसकी बुनियाद निष्पक्षता, स्वतंत्रता, तथ्यपरकता और जनहित पर टिकी होती है। पत्रकार का दायित्व सत्ता से सवाल पूछना, व्यवस्था की खामियों को उजागर करना और समाज के सामने तथ्यों को प्रस्तुत करना है लेकिन जब पत्रकारिता के मूल्यों पर राजनीतिक हित हावी होने लगें, तब उसकी स्वतंत्रता, विश्वसनीयता और मयार्दा को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। आज जंतर-मंतर से लेकर न्यायालयों तक पत्रकारिता की परिभाषा, मान्यता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर जारी बहस इसी व्यापक संदर्भ में देखी जानी चाहिए। राजनीतिक दल और नेताओं को पत्रकारिता से असहमति हो सकती है, उन्हें खबर, टिप्पणी और सवालों पर आपत्ति जताने का अधिकार भी है लेकिन पत्रकारिता की कसौटी राजनीतिक सुविधा नहीं हो सकती, यदि किसी पत्रकार से यह अपेक्षा की जाय कि वह किसी नेता या दल के पक्ष में ही लिखे, उसकी उपलब्धियों का गुणगान करे और उसकी कमियों पर मौन रहे तो यह पत्रकारिता नहीं है।

डिजिटल तकनीक ने सूचना के प्रसार को आसान बना दिया है। आज कोई भी नागरिक मोबाइल फोन से घटनाओं का वीडियो बना सकता है, सोशल मीडिया पर सामग्री साझा कर सकता है और किसी मुद्दे को व्यापक चर्चा का विषय बना सकता है। यह लोकतंत्र के लिए उपयोगी बदलाव है। नागरिक पत्रकारिता ने कई ऐसे मुद्दों को भी सामने लाने में मदद की है, जिन्हें मुख्यधारा का मीडिया पर्याप्त स्थान नहीं दे पाता, लेकिन किसी घटना का वीडियो बनाना, रील तैयार करना या सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना और पेशेवर पत्रकारिता करना एक ही बात नहीं है। पत्रकारिता में तथ्यों की पुष्टि, स्रोतों की जांच, संबंधित पक्षों का दृष्टिकोण, संदर्भ की समझ, कानूनी सीमाओं का ज्ञान और प्रकाशित सामग्री के प्रति जवाबदेही भी शामिल होती है। केवल व्यूज, लाइक्स और फॉलोअर्स की संख्या किसी व्यक्ति को विश्वसनीय पत्रकार नहीं बना देती इसीलिए स्वतंत्र पत्रकार, फ्रीलांसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों और रील बनाने वालों की भूमिकाओं पर गंभीर चर्चा आवश्यक है। इन सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है लेकिन उनकी कार्यप्रणाली, पेशेवर जिम्मेदारियां और किसी संवेदनशील स्थल पर प्रवेश की पात्रता अलग-अलग हो सकती हैं। इस अंतर को समझना किसी की स्वतंत्रता का विरोध करना नहीं बल्कि पत्रकारिता की प्रकृति और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना है।

16 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों, स्वतंत्र पत्रकारों और रील बनाने वालों की पहचान तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई के दौरान कहा कि यदि हर नागरिक पत्रकार बनने लगे तो इससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने पत्रकारों की विभिन्न श्रेणियों और उन्हें मिलने वाली सुरक्षा के स्तर पर विस्तृत विचार की जरूरत बताई।। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठाया कि विरोध-प्रदर्शनों को कवर करने वाले स्वतंत्र और फ्रीलांस पत्रकारों से पुलिस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) का कार्ड मांगती है और उनकी पेशेवर पहचान को लेकर कठिनाइयां पैदा होती हैं। दूसरी ओर, अदालत के समक्ष यह सवाल भी आया कि स्वतंत्र पत्रकारों और सोशल मीडिया पर सामग्री बनाने वालों के बीच अंतर कैसे किया जाय। इस बहस का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा के साथ-साथ वास्तविक पत्रकारों की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट प्रक्रिया होनी चाहिए। इस प्रकरण ने एक बुनियादी प्रश्न खड़ा किया है। क्या विरोध-प्रदर्शनों में पत्रकारों की मौजूदगी का उद्देश्य केवल किसी राजनीतिक आंदोलन को अधिक दृश्यता दिलाना है या वहां होने वाली घटनाओं की निष्पक्ष रिपोर्टिंग करना भी है। यदि किसी प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद हैं और उसके साथ सोशल मीडिया कंटेंट निमार्ता भी पहुंचते हैं तो दोनों की भूमिका और जिम्मेदारी को स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आतंकी चेहरा सुरक्षा को लेकर नई चुनौती

डॉ. अनिल कुमार निगम

> भारत को एआई के संभावित दुरुपयोग से निपटने के लिए केवल प्रतिबंधों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। साइबर सुरक्षा, ड्रोन पहचान, डिजिटल फॉरेंसिक और संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों के विश्लेषण की क्षमताओं को मजबूत करना आवश्यक है। एआई आधारित प्रणालियां सुरक्षा एजेंसियों को उपयोगी संकेत दे सकती हैं लेकिन अंतिम निर्णय में मानवीय जांच और कानूनी प्रक्रिया की भूमिका अनिवार्य होनी चाहिए।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अब केवल विकास और नवाचार का औजार नहीं रहा, उसका दुरुपयोग आतंकवाद की पहुंच, प्रचार और प्रभाव को बढ़ाने का माध्यम भी बन सकता है। जिस तकनीक से दुनिया ज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा और रक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही है, वही तकनीक आतंकवादी संगठनों के हाथों में पड़कर सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर सकती है। सवाल यह नहीं कि एआई उपयोगी है या खतरनाक बल्कि यह है कि इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए दुनिया कितनी तैयार है।

ब्रिटेन की घरेलू खुफिया एजेंसी टक्ष के प्रमुख सर केन मैक्कलम ने हाल ही में 2026 में एआई के दुरुपयोग से जुड़े आतंकवादी खतरों पर चिंता जताई है। यह चेतावनी भारत सहित उन सभी देशों के लिए प्रासंगिक है, जहां आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और डिजिटल दुष्प्रचार राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एआई का खतरा केवल हथियारों के स्वचालन तक सीमित नहीं है, यह झूठ को सच जैसा दिखाने, नफरत फैलाने और समाज के विश्वास को कमजोर करने की क्षमता भी रखती है। परंपरागत आतंकवाद हथियारों, विस्फोटकों, गुप्त नेटवर्क और प्रशिक्षित मानव संसाधन पर निर्भर रहा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने आतंकवादी संगठनों को प्रचार और भर्ती के नए रास्ते दिए। अब जनरेटिव एआई इस डिजिटल तंत्र को अधिक तेज और व्यापक बना सकती है। बहुभाषी प्रचार सामग्री तैयार करना, नकली आवाजें और वीडियो बनाना तथा अलग-अलग समुदायों को लक्षित करने वाले संदेश तैयार करना पहले की तुलना में आसान हो सकता है।

संयुक्त राष्ट्र के अंतरक्षेत्रीय अपराध एवं न्याय अनुसंधान संस्थान (यूएनआईसीआरआई) और संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-रोधी केंद्र (यूएनसीसीटी) की रिपोर्ट Algorithms and Terrorism: The Malicious Use of Artificial Intelligence for Terrorist Purposes ने एआई के इसी दोहरे उपयोग के प्रति आगाह किया है। तकनीक की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसका वैध इस्तेमाल करने वाले और उसका दुरुपयोग करने वाले, दोनों, समान डिजिटल साधनों तक पहुंच बना सकते हैं। इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) ने सोशल मीडिया, वीडियो और ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए अपने प्रचार तथा भर्ती को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिया। उसका डिजिटल प्रचार एआई के व्यापक प्रसार से पहले शुरू हुआ था लेकिन आज एआई आधारित अनुवाद और सामग्री निर्माण जैसी क्षमताएं ऐसी रणनीतियों को अधिक भाषाओं और समुदायों तक पहुंचाने में मदद कर सकती हैं। यह अंतर समझना जरूरी है कि आईएसआईएस का पुराना डिजिटल प्रचार एआई के इस्तेमाल का प्रमाण नहीं, बल्कि उस डिजिटल पारिस्थितिकी का उदाहरण है जिसे एआई और अधिक प्रभावी बना सकती है।

अक्टूबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय (सीटीईडी) ने आतंकवाद और आतंकवाद-रोधी प्रयासों के संदर्भ में एआई के जोखिमों तथा अवसरों पर विशेषज्ञ चर्चा की थी। इस पहल ने स्पष्ट किया कि एआई का दुरुपयोग अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए संभावित खतरा है। एआई के खुले मॉडलों और उनकी सुरक्षा पर होने वाले शोध से भी चिंता बढ़ी है। यदि सुरक्षा प्रतिबंधों को दरकिनार कर हानिकारक सामग्री तैयार की जाती है तो तकनीक का दुरुपयोग बढ़ सकता है।

भारत के संदर्भ में एआई और आतंकवाद का प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। देश की विशाल डिजिटल आबादी, सीमापार आतंकवाद की चुनौती और सामाजिक विविधता ऐसी परिस्थितियां पैदा करती हैं, जिनमें डिजिटल दुष्प्रचार के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। पहला खतरा, डीपफेक और सामाजिक अस्थिरता है। किसी नेता, सैन्य अधिकारी या धार्मिक व्यक्तित्व की नकली आवाज अथवा वीडियो को वास्तविक बताकर प्रसारित किया जाए तो इससे भ्रम, तनाव और अविश्वास पैदा हो सकता है। संवेदनशील घटनाओं के दौरान ऐसी सामग्री कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती है। दूसरा खतरा, सीमापार आतंकवाद का डिजिटल विस्तार है। एआई की मदद से बहुभाषी प्रचार और भ्रामक संदेश तैयार करना आसान हो सकता है। इससे आतंकवादी विचारधारा का प्रसार, युवाओं को प्रभावित करने के प्रयास और ऑनलाइन कट्टरपंथ की समस्या अधिक जटिल हो सकती है।

तीसरा खतरा, ड्रोन और साइबर सुरक्षा है। एआई सक्षम ड्रोन तथा स्वचालित तकनीकों का दुरुपयोग सीमावर्ती क्षेत्रों और संवेदनशील प्रतिष्ठानों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। इसी तरह बिजली, संचार, परिवहन और बैंकिंग जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले व्यापक व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। चौथा खतरा, सूचना पर विश्वास का संकट है। जब नकली वीडियो और कृत्रिम आवाजें असली जैसी दिखाई देने लगें तो नागरिकों के लिए सही और गलत में अंतर करना कठिन हो सकता है। आतंकवादियों के लिए यह स्थिति भय फैलाने और संस्थाओं की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाने का अवसर बन सकती है।

भारत को एआई के संभावित दुरुपयोग से निपटने के लिए केवल प्रतिबंधों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। साइबर सुरक्षा, ड्रोन पहचान, डिजिटल फॉरेंसिक और संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों के विश्लेषण की क्षमताओं को मजबूत करना आवश्यक है। एआई आधारित प्रणालियां सुरक्षा एजेंसियों को उपयोगी संकेत दे सकती हैं लेकिन अंतिम निर्णय में मानवीय जांच और कानूनी प्रक्रिया की भूमिका अनिवार्य होनी चाहिए। डीपफेक और फर्जी खबरों के विरुद्ध त्वरित तथ्य-जांच व्यवस्था विकसित करनी होगी। तकनीकी कंपनियों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग, एआई मॉडलों की सुरक्षा जांच तथा दुरुपयोग की रिपोर्टिंग को मजबूत करना भी जरूरी है। साथ ही, युवाओं में डिजिटल साक्षरता बढ़ानी होगी, ताकि वे भड़काऊ सामग्री और भ्रामक प्रचार को बिना जांचे साझा न करें। एआई को आतंकवाद का सुपरचार्जर बनने से रोकना केवल तकनीकी चुनौती नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक विश्वास और लोकतांत्रिक जवाबदेही की परीक्षा है।

देश विरोध का खतरनाक खेल खेलते राहुल गांधी

डॉ. मयंक चतुवेर्दी

वस्तुतः राहुल गांधी और उनके सहयोगियों को इस मामले में दक्षिण के राजनेता कमल हासन के उन देशभक्तिपूर्ण शब्दों से सीख लेनी चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कोई उपनिवेश नहीं। हमारे यहां दुनिया का स्वागत है परंतु अपने भविष्य का फैसला भारत की जनता करेगी, पश्चिमी स्वार्थ या कोई विदेशी अरबपति नहीं। ऐसे में कहना यही है कि देश की जनता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रची जा रही इस टूलकिट और साजिश को भली-भांति समझ रही है और वह अपने लोकतंत्र की रक्षा विदेशी बैसाखियों के बिना, स्वयं करने में पूरी तरह सक्षम है। राहुल गांधी विचार करें, वे इस अराजकता से आखिर क्या प्राप्त कर लेंगे।



पिछले कुछ समय से देश में राजनीति का ऐसा विकृत स्वरूप उभर रहा है, जो देश की संप्रभुता के लिए गंभीर चेतावनी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब घरेलू राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं देश की सीमाओं को लांघकर विदेशी ताकतों, अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट्स और वैश्विक संस्थाओं की दहलीज पर समर्थन मांगने लगें तो वह लोकतंत्र को खोखला करती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा विदेशी धरती पर जाकर भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर दिए गए बयान, एलन मस्क जैसे दंभी विदेशी अरबपतियों की भारत-विरोधी झुंझलाहट और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय जैसी संस्थाओं का पक्षपातपूर्ण रवैया, वस्तुतः यह सब किसी संयोग का हिस्सा नहीं लगते। एक के बाद एक चुनावों में पराजय झेलने के बाद घरेलू राजनीति में अस्थिरता पैदा करने और चुनी हुई मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए विदेशी शक्तियों के साथ जो परोक्ष जुगलबंदी दिखाई दे रही है, वह देश के आंतरिक मामलों में बाहरी दखल को खुला निमंत्रण है।

भारतीय लोकतंत्र में सत्ता का परिवर्तन हमेशा जनता के मतों से तय होता है। परंतु, विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा अंतरराष्ट्रीय मंचों का उपयोग देश की चुनाव प्रणाली, न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लांछित करने के लिए किया जाना अत्यंत चिंताजनक है। उनके बयानों में बार-बार यह राग अलापा गया कि पश्चिमी देश भारत में 'लोकतंत्र की पुनर्स्थापना' के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। यह अपील परोक्ष रूप से विदेशी ताकतों को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आमंत्रण देने जैसी है।

दूसरी ओर जब एक जिम्मेदार राष्ट्रीय नेता विदेशी धरती पर जाकर अपनी ही संवैधानिक संस्थाओं को 'कमजोर' बताता है, तो वह उन वैश्विक ताकतों का हौसला बढ़ाता है जो भारत की मजबूत वैश्विक छवि और आर्थिक प्रगति से ईर्ष्या करती हैं। वस्तुतः इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खतरनाक मोड़ तब देखने में आता है जब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क जैसे विदेशी कारोबारी भारतीय संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। मस्क की कंपनी 'स्टारलिंक' भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए लाइसेंस चाहती है किंतु भारत सरकार ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और नियामक पैमानों पर किसी भी प्रकार का समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। मस्क ने अपनी इस व्यावसायिक खीझ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भारतीय नीतियों और स्वदेशी उद्यमियों (जैसे मुकेश अंबानी) के खिलाफ विषवमन करके निकाला। मस्क का यह चरित्र ही रहा है कि वे अपने व्यापारिक हितों के लिए किसी भी देश के लोकतंत्र को मटियामेट करने की दंभपूर्ण सोच रखते हैं, जैसा कि बोलीविया के लीथियम भंडार पर कब्जा करने के लिए वहां के निर्वाचित राष्ट्रपति के खिलाफ रचे गए तख्तापलट की साजिश में उनकी स्वीकारोक्ति (हम जिसका चाहें तख्तापलट करेंगे) से सामने भी आ चुका है।

सबसे बड़ा इसमें दुखद पहलू यह है कि राहुल गांधी इस मामले में भारत सरकार की सुरक्षा नीतियों के साथ खड़े होने के बजाय मस्क की भारत-विरोधी भावनाओं के साथ सुर मिलाते और उन्हें उकसाते नजर आए। ऐसे में कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीति का एक बड़ा विरोधाभास यह है कि वे देश के भीतर रोजगार, बुनियादी ढांचा और पूंजी का निर्माण करने वाले भारतीय उद्यमियों (अडानी-अंबानी) को दिन-रात लांछित करते हैं, पर वहीं एलन मस्क जैसे बदमिजाज और मयार्दाहीन विदेशी उद्योगपति के आर्थिक स्वार्थों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं।

इससे पहले जब अमेरिकी राजनेता डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 'डेड इकोनॉमी' कहकर अपमानित करने का प्रयास किया, तब भी राहुल गांधी ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा भारतीय विकास दर के सकारात्मक और मजबूत अनुमानों को दरकिनार कर ट्रंप के दावों से सहमति जताने में देर नहीं लगाई। विदेशी कारपोरेट्स के आगे इस प्रकार नतमस्तक होना और स्वदेशी उद्योगों की साख गिराना देश के आर्थिक स्वावलंबन पर सीधा प्रहार है।

इसी तरह से लोकतंत्र की अंतिम रक्षा-पंक्ति उसकी स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, मगर अब उसे भी सड़क के हंगामे और राजनीतिक प्रदर्शनों के दबाव में लेने का एक खतरनाक चलन शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन एक मामले के दौरान राहुल गांधी द्वारा मुख्य न्यायाधीश से व्यक्तिगत रूप से मिलने की इच्छा जताना और अनुमति न मिलने पर विपक्षी नेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च करना, कानून व्यवस्था का खुला मखौल उड़ाना नहीं तो क्या है? पुलिस-प्रशासन को चकमा देकर याचिका सौंपने के इस नए तरीके ने आंदोलनों की प्रकृति को पूरी तरह विकृत कर दिया है।

अब यह कोई संयोग नहीं है कि जब देश के भीतर अराजकता और आंदोलनों के जरिए मोदी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास तेज होता है, ठीक उसी समय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय जैसी वैश्विक संस्थाएं भारत को लोकतांत्रिक मूल्यों पर ज्ञान देना शुरू कर देती हैं। इस एजेंसी के दोहरे रवैये की जितनी आलोचना की जाए, वह कम है। जब भारत के पड़ोसियों, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का खुलेआम कत्लेआम होता है, मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और चुनी हुई सरकारों का हिंसक तख्तापलट होता है, तब ये वैश्विक पदाधिकारी मौन साध लेते हैं परंतु भारत में संसद द्वारा पास किए गए कानूनों या न्यायिक प्रक्रियाओं पर ये तुरंत हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं!

इससे इस बात की पुष्टि होती है कि भारतीय लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए देश के भीतर की कुंठित राजनीतिक ताकतों और देश के बाहर बैठे पश्चिमी स्वार्थों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं व मस्क जैसे विदेशी अरबपतियों के बीच एक साठगांठ मजबूत होती जा रही है। घरेलू स्तर पर वैचारिक मतभेद कितने भी गहरे क्यों न हों, जब बात देश की संप्रभुता और सम्मान की आती है, तो किसी भी बाहरी शक्ति को जज बनने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। कम से कम इतना तो राहुल गांधी जैसे विपक्ष के मुख्य नेता को समझना चाहिए।

वस्तुतः राहुल गांधी और उनके सहयोगियों को इस मामले में दक्षिण के राजनेता कमल हासन के उन देशभक्तिपूर्ण शब्दों से सीख लेनी चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कोई उपनिवेश नहीं। हमारे यहां दुनिया का स्वागत है परंतु अपने भविष्य का फैसला भारत की जनता करेगी, पश्चिमी स्वार्थ या कोई विदेशी अरबपति नहीं। ऐसे में कहना यही है कि देश की जनता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रची जा रही इस टूलकिट और साजिश को भली-भांति समझ रही है और वह अपने लोकतंत्र की रक्षा विदेशी बैसाखियों के बिना, स्वयं करने में पूरी तरह सक्षम है। राहुल गांधी विचार करें, वे इस अराजकता से आखिर क्या प्राप्त कर लेंगे।

श्रीमती नीरजा पाटिलः मत्स्य आहार उद्योग से लेकर फ्लोटिंग फिश केज निर्माण तक उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की प्रेरक मिसाल

नवाचार, दृढ़ संकल्प और सरकारी योजनाओं के सहयोग से सफलता की नई इबारत

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

नीरजा पाटिल एक ऐसी महिला उद्यमी हैं, जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प, मेहनत और दूरदर्शी सोच के बल पर मत्स्य पालन क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उन्होंने न केवल मत्स्य आहार उद्योग की स्थापना कर मत्स्य कृषकों के लिए आहार की उपलब्धता सुनिश्चित की, बल्कि अपने उद्यम का विस्तार करते हुए फ्लोटिंग फिश केज निर्माण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण पहल की है। उनकी यह सफलता महिला उद्यमिता, स्वरोजगार और मत्स्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास का प्रेरणादायक उदाहरण है। अपने उद्यम की स्थापना के उद्देश्य से श्रीमती नीरजा पाटिल ने राजगढ़ जिले का भ्रमण किया। इस दौरान उनकी मुलाकात सहायक संचालक, मत्स्योद्योग, जिला राजगढ़ से हुई। विभागीय अधिकारियों के संपर्क में आने पर उन्हें भारत सरकार द्वारा संचालित नीली क्रांति योजना के अंतर्गत मत्स्य क्षेत्र में उपलब्ध उद्यम स्थापना की संभावनाओं की जानकारी प्राप्त हुई। योजना का अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने मत्स्य आहार निर्माण इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य से उन्होंने मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम औद्योगिक क्षेत्र पीलूखेड़ी, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ में प्लॉट/शेड क्रमांक 22 (ष्ठ) पर 3,900 वर्ग मीटर का भूखंड लीज पर प्राप्त किया। इसके पश्चात उन्होंने मत्स्य आहार मिल की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर कार्यालय सहायक संचालक, मत्स्योद्योग, जिला राजगढ़ में आवेदन प्रस्तुत किया। तत्कालीन सहायक संचालक



मत्स्योद्योग द्वारा उनके प्रस्ताव को जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित कराने के उपरांत परियोजना का कार्य पूर्ण कर मूल्यांकन हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। मत्स्य आहार निर्माण इकाई की स्थापना के दौरान कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद श्रीमती पाटिल ने हार नहीं मानी। मत्स्य विभाग के निरंतर मार्गदर्शन एवं सहयोग से उन्होंने परियोजना का कार्य आगे बढ़ाया और अंततः दिनांक 13 अप्रैल 2022 को परियोजना पूर्ण कर मूल्यांकन प्रतिवेदन कार्यालय सहायक संचालक, मत्स्योद्योग, जिला राजगढ़ में प्रस्तुत किया। उनकी यह उपलब्धि दर्शाती है कि उचित मार्गदर्शन, योजनाबद्ध प्रयास और दृढ़ इच्छाशक्ति से विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। श्रीमती नीरजा पाटिल द्वारा स्थापित मत्स्य आहार मिल आज मत्स्य पालन क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जिले में सघन मत्स्य पालन के प्रति बढ़ते रुझान के बीच इस इकाई ने मत्स्य कृषकों को गुणवत्तापूर्ण मत्स्य आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने में योगदान दिया है। इस इकाई के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 10 टन उत्पादन क्षमता के आधार पर मत्स्य आहार की आपूर्ति की जा रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इकाई द्वारा लगभग 250 से 300 टन मत्स्य आहार की पूर्ति की जा रही है। यहां निर्मित मत्स्य आहार की आपूर्ति मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों में भी की जा रही है। इस उद्यम से हितग्राही को लगभग 87 लाख से 105 लाख रुपये तक का वार्षिक व्यवसाय प्राप्त हो रहा है। इससे मत्स्य पालन क्षेत्र को आवश्यक इनपुट उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर औद्योगिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिला है। नीरजा पाटिल ने मत्स्य आहार उद्योग की सफलता तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने पति श्री दिलीप पाटिल के साथ मिलकर फ्लोटिंग फिश केज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की दिशा में भी कदम बढ़ाया। इस पहल के माध्यम से मत्स्य पालन के लिए आवश्यक केज निर्माण में उपयोग होने वाले पंटून एवं अन्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिला सोलर ऑवर में 20 प्रतिशत छूट का लाभ

विदिशा के 67 हजार 321 उपभोक्ताओं को सितंबर माह में 45 लाख 66 हजार की छूट

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनके मासिक विद्युत बिल में टाइम ऑफ डे छूट का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में सितंबर 2026 के दौरान विदिशा के कुल 67 हजार 321 उपभोक्ताओं को 45 लाख 66 हजार रुपए की रियायत प्रदान की गई है। कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनकी विद्युत खपत के आधार पर टाइम ऑफ डे योजना के अंतर्गत यह छूट प्रदान की गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री ऋषि गर्ग ने बताया है कि कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटरिंग पहल के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सोलर ऑवर में बिजली उपयोग करने पर विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दिन के टैरिफ में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के



लिए यह सभी छूट अथवा प्रोत्साहन की गणना सरकारी सब्सिडी (यदि कोई हो) को छोड़कर की जा रही है। कंपनी ने बताया है कि घरेलू, गैर घरेलू, सार्वजनिक जल कार्य, स्ट्रीट लाइट एवं निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि को सोलर ऑवर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उपभोग की गई ऊर्जा पर ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर में 20 प्रतिशत तक की छूट 10 किलोवाट तक स्वीकृत लोड/अनुबंध मांग वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही है। प्रबंध संचालक श्री ऋषि गर्ग ने आमजन एवं उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने परिसरों में स्मार्ट मीटर लगाने में सहयोग करें तथा स्मार्ट मीटर के उपयोग से होने वाले लाभों का अधिक से अधिक फायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर से सटीक रीडिंग, पारदर्शी बिलिंग एवं ऊर्जा खपत की रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव हो रही है। उल्लेखनीय है कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को बिजली की खपत को ट्रैक करने, ऊर्जा बचत करने तथा मोबाइल एप के माध्यम से कहीं से भी अपनी खपत की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। यह प्रणाली ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक सिद्ध हो रही है। ऊर्जा की खपत को ट्रैक कर नियंत्रित करने और ऊर्जा की बचत करने में मदद करता है। बिजली की खपत को सटीक रूप से मापता है, जिससे बिल में कोई गलती नहीं होती। एप के जरिए मोबाइल पर रियल-टाइम डेटा देखकर ऊर्जा की खपत को नियंत्रित कर सकते हैं। ऊर्जा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलती है, ताकि ऊर्जा की खपत को बेहतर बना सकते हैं। ऑनलाइन ट्रैक करने और नियंत्रित करने की सुविधा मिलती है। ऊर्जा की खपत को कम करने से पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव कम होता है।

सह-चिकित्सीय क्षेत्र में दक्ष मानव संसाधन तैयार करने के लिए आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यकः उप मुख्यमंत्री शुक्ल



■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने के लिए सह-चिकित्सीय क्षेत्र में दक्ष एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों और तकनीकों के अनुरूप युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में एलाइड एंड हेल्थकेयर पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जाए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने वल्लभ भवन में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में राष्ट्रीय एलाइड एंड हेल्थकेयर आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी अंतरिम दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए आयोग द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों को मध्यप्रदेश में तत्काल प्रभाव से प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबद्धता एवं प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करें। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आयोग द्वारा एलाइड एंड हेल्थकेयर पाठ्यक्रमों के माध्यम से सह-चिकित्सीय क्षेत्र में उन्नयन, आधुनिक तकनीक के विस्तार तथा देशभर में पाठ्यक्रमों में एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंतरिम दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

600 रुपए पेंशन के लिए मोहताज बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग, सरकार की प्राथमिकताओं परः रमाकांत

■ एक सत बुलेटिन, **रायसेन**

आम आदमी की आर्थिक परेशानियों और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के प्रवक्ता रमाकांत पटेल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया कि एक ओर सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर वृद्धजन, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को मिलने वाली 600 रुपए मासिक पेंशन भी कई-कई महीनों तक नहीं मिल रही है। रमाकांत पटेल ने कहा कि वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन जरूरतमंद लोगों के लिए आर्थिक सहारा है। कई लोग इसी राशि से अपनी रोजमर्रा की छोटी-मोटी जरूरतें पूरी करते हैं और भोजन की व्यवस्था करते हैं। ऐसे में यदि उन्हें कई महीनों तक पेंशन नहीं मिलती, तो उनके सामने गंभीर और आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश सरकार अपने प्रचार-प्रसार और साज-सज्जा पर बड़ी रकम खर्च कर रही है, लेकिन जरूरतमंद हितग्राहियों को समय पर पेंशन उपलब्ध कराने में लापरवाही बरती जा रही है। पटेल ने कहा कि महंगाई के इस दौर में 600 रुपए की राशि भी गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यही



राशि समय पर नहीं मिलेगी, तो वे अपनी बुनियादी जरूरतें कैसे पूरी करेंगे। आप प्रवक्ता ने सरकार से मांग की कि वृद्धजन, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों की लंबित पेंशन का भुगतान जल्द किया जाए तथा भविष्य में पेंशन नियमित रूप से उनके खातों में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता समय पर मिलना चाहिए, ताकि उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशान न होना पड़े।

पुलिस गरबा महोत्सव में 1100 महिलाओं ने दी प्रस्तुतियां

भोपाल। पुलिस परिवारजनों के बीच आपसी सौहार्द, उत्साह और सांस्कृतिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय की कल्याण शाखा द्वारा पुलिस लाइन, नेहरू नगर में मध्यप्रदेश पुलिस गरबा महोत्सव आयोजित किया गया। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने मां अम्बे की आरती कर महोत्सव का शुभारंभ किया।महोत्सव में भोपाल जिला पुलिस बल, सातवीं, 23वीं और 25वीं वाहिनी के पुलिस परिवारों की 1100 से अधिक महिलाओं और बच्चियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने धार्मिक और फिल्मी धुनों पर पारंपरिक गरबा नृत्य की प्रस्तुतियां दीं। इस अवसर पर सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना, वरिष्ठ अधिकारी जीपी सिंह, पुलिस आयुक्त संजय कुमार सहित अन्य अधिकारी और उनके परिजन मौजूद रहे।

मां हरसिद्धि मंदिर तरावली कला में नवरात्रि महोत्सव का उत्साहः चुनरी यात्राओं से भक्तिमय हुआ माहौल

■ एक सत बुलेटिन, **बैरसिया।**

क्षेत्र के प्रसिद्ध प्राचीन धार्मिक धाम मां हरसिद्धि मंदिर तरावली कला में नवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। जहां माता रानी के दर्शन और पूजन के लिए क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण अंचलों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। वहीं अलग-अलग गांवों से निकाली जा रही भव्य चुनरी यात्राएं मां के दरबार में पहुंचकर आस्था और उत्साह का माहौल बना रही हैं। नवरात्रि महोत्सव के दौर5न मंदिर परिसर में भक्तों की चहल-पहल बनी हुई है। श्रद्धालु मां हरसिद्धि की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और क्षेत्र की उन्नति की कामना कर रहे हैं। डीजे ढोल नगाड़ों के साथ चुनरी यात्राओं में



श्रद्धालु नृत्य करते हुए पूरे उत्साह और भक्तिभाव के साथ शामिल होकर माता रानी के जयकारे लगाते हुए मंदिर पहुंच रहे हैं मां हरसिद्धि मंदिर तरावली कला क्षेत्र के श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। नवरात्रि के अवसर पर यहां का धार्मिक वातावरण भक्तिमय हो जाता है और दूर-दराज के गांवों से भी श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ और चुनरी यात्राओं की भव्यता क्षेत्र की धार्मिक परंपरा, सामाजिक एकता और माता रानी के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाती है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर पूरा क्षेत्र माता की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं के लिए मां हरसिद्धि का दरबार आस्था,विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।

दिल्ली स्थित निवास पर की आत्मीय मुलाकात, एक दशक पुराने संबंधों को याद कर की व्यक्तित्व और कार्यशैली की सराहना

सादगी और संगठन के प्रति समर्पण की मिसाल हैं डॉ.एल.मुरुगनः विनय मेहर

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

जिला पंचायत सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं भोपाल जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर ने नई दिल्ली स्थित निवास पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ.एल. मुरुगन से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने डॉ. मुरुगन के साथ अपने लगभग एक दशक पुराने संबंधों को याद करते हुए उनके सादगीपूर्ण व्यक्तित्व, संगठन के प्रति समर्पण और कार्यकर्ताओं के साथ आत्मीय व्यवहार की सराहना की। विनय मेहर ने बताया कि उनकी पहली मुलाकात करीब 10 वर्ष पूर्व भोपाल में हुई थी। उस समय डॉ.एल.मुरुगन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। इसके बाद से उन्होंने डॉ.मुरुगन के राजनीतिक सफर को करीब से देखा है। मेहर के अनुसार, विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचने के बावजूद डॉ. मुरुगन की सहजता, सरलता और कार्यकर्ताओं के प्रति अपनत्व में कोई बदलाव नहीं आया है। साधारण परिवार से राष्ट्रीय राजनीति तक का प्रेरणादायक सफर विनय मेहर ने कहा कि एक साधारण मजदूर परिवार से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करना डॉ.एल. मुरुगन के संघर्ष,मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिचायक है। उन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में भी



महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। मेहर ने कहा कि डॉ. मुरुगन का जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणास्रोत है,जो संगठन और समाज के लिए समर्पित भाव से कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका सफर बताता है कि निरंतर परिश्रम, संगठन के प्रति निष्ठा और समर्पण के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई जा सकती है। बड़े पदों पर पहुंचने के बाद भी कार्यकर्ताओं से वही अपनत्व विनय मेहर ने कहा कि डॉ.एल.मुरुगन के साथ उनके संबंध केवल राजनीतिक नहीं हैं, बल्कि उनमें पारिवारिक आत्मीयता और छोटे भाई जैसा स्नेह भी शामिल है। महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बावजूद कार्यकर्ताओं की बात सुनना, उन्हें प्रोत्साहित करना और उनके साथ सहजता से मिलना डॉ. मुरुगन के व्यक्तित्व की खास विशेषता है। उन्होंने कहा कि राजनीति में पद और जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं, लेकिन व्यक्ति का व्यवहार, आपसी विश्वास और संबंधों में बना सम्मान ही उसकी वास्तविक पहचान होती हैं। डॉ. मुरुगन का कार्यकर्ताओं के प्रति स्नेह और सरल सहज व्यवहार उन्हें विशिष्ट बनाता है। डॉ. मुरुगन से मिला स्नेह और सम्मान जीवनभर याद रहेगा : मेहर विनय मेहर ने भावुकता के साथ कहा कि डॉ. एल.मुरुगन ने उन्हें हमेशा छोटे भाई की तरह स्नेह और सम्मान दिया है। उनके द्वारा मिले इस अपनत्व और मार्गदर्शन को वे जीवनभर नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि डॉ. मुरुगन से मुलाकात उनके लिए हमेशा गौरव और सौभाग्य का विषय रही है। मेहर ने विश्वास जताया कि डॉ. मुरुगन का स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद भविष्य में भी उन्हें संगठनात्मक गतिविधियों तथा जनसेवा के कार्यों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेतृत्व से मिलने वाला मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाता है और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को और मजबूत करता है।

संक्षिप्त समाचार

30 नवंबर तक निपटा लें पेंशनभोगी यह काम, चूके तो अटक सकती है हर महीने मिलने वाली पेंशन



नई दिल्ली, एजेंसी। देश के करोड़ों पेंशनभोगियों के लिए हर साल एक बेहद जरूरी प्रक्रिया पूरी करने का समय आ गया है। यदि आपने समय रहते अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया, तो आपकी पेंशन रुक सकती है। पेंशन और पेंशनभोगियों के कल्याण विभाग के नियमों के अनुसार, इसके लिए अलग-अलग आयु वर्ग के हिसाब से तारीखें तय की गई हैं। जीवन प्रमाण एक सरकारी डिजिटल सुविधा है, जो पेंशनभोगियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देती है। इससे बुजुर्गों को बार-बार बैंक शाखाओं के चक्कर काटने से राहत मिलती है। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के अति-वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की खिड़की एक अक्तूबरसे खुल चुकी है।

80 वर्ष से कम उम्र के अन्य सभी पेंशनभोगी एक नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपना प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। सभी पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर निर्धारित की गई है। अब बुजुर्गों को लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। सरकार की जीवन प्रमाण सुविधा के जरियेआप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन से ही घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। जरूरी चीजें- आपका आधार नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर, सक्रिय मोबाइल नंबर और बैंक खाते का विवरण।

नेटफ्लिक्स में बड़ी छंटनी की खबर! करीब 1,000 कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी

नई दिल्ली, एजेंसी। दुनिया की बड़ी स्ट्रीमिंग कंपनियों में शामिल नेटफ्लिक्स करीब 1,000 कर्मचारियों की नौकरियों में कटौती करने जा रही है। यह संख्या कंपनी की ग्लोबल वर्कफोर्स का लगभग 6 प्रतिशत है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 के बाद नेटफ्लिक्स में छंटनी का यह सबसे बड़ा दौर है। कंपनी के को-सीइओ ग्रेग पीटर्स और टेड सारंडोस ने बुधवार सुबह कर्मचारियों को ईमेल भेजकर इस फैसले की जानकारी दी। खास बात यह है कि कंपनी अपने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित करने से करीब एक सप्ताह पहले यह कदम उठा रही है।

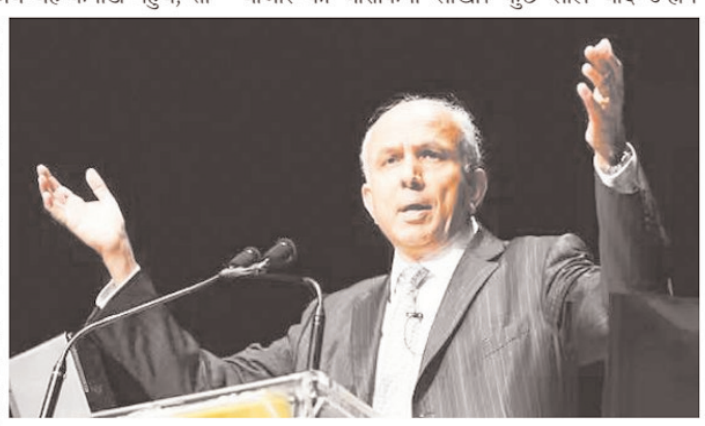
नेटफ्लिक्स में किन विभागों पर पड़ेगा छंटनी का असर: रिपोर्ट के अनुसार, छंटनी का सबसे ज्यादा असर प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, लीगल और एचआर विभागों पर पड़ सकता है। पिछले साल के अंत तक नेटफ्लिक्स में करीब 16,000 फुल-टाइम कर्मचारी काम कर रहे थे। कंपनी के प्रमुखों ने कर्मचारियों से कहा कि नेटफ्लिक्स अपने कारोबार के उन क्षेत्रों में निवेश जारी रखेगी, जहां से सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इसके लिए कर्मचारियों और पैसों के इस्तेमाल को लेकर ज्यादा सोच-समझकर फैसले लेने होंगे। कंपनी ने यह भी कहा है कि वह पूरे साल की कमाई के अपने अनुमान को पूरा करने की राह पर है।

नेटफ्लिक्स में इससे पहले जून 2022 में बड़े स्तर पर छंटनी हुई थी। उस समय कंपनी ने एक दशक से अधिक समय में पहली बार किसी तिमाही में अपने सब्सक्राइबर्स की संख्या में गिरावट दर्ज की थी। इस बार भी कंपनी ऐसे दौर में कर्मचारियों की संख्या घटा रही है, जब उसके शेयरों पर दबाव है और दर्शकों की देखने की आदतों में अपेक्षित तेजी नहीं दिख रही है।

सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन देखने का समय बढ़ाना चुनौती: नेटफ्लिक्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल ग्राहक बनाए रखने की नहीं, बल्कि उन्हें ज्यादा समय तक अपने प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने की भी है। कंपनी के पास करीब 32.5 करोड़ पेड मेंबर्स हैं। अमेरिका में नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन कैंसिलेशन दर 2 प्रतिशत से थोड़ी ज्यादा है, जो इंडस्ट्री में सबसे कम बताई गई है। हालांकि, दर्शकों के देखने के कुल समय में बढ़ोतरी धीमी रही है।

कभी सिर्फ 760 रुपये लेकर पहुंचे थे कनाडा, अब 53000 करोड़ में खरीदा आईडीबीआई बैंक

नई दिल्ली, एजेंसी। हैदराबाद के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे प्रेम वत्स आज कनाडा की वित्तीय दुनिया के बड़े नामों में शामिल हैं। जब वह कनाडा पहुंचे, तो उनकी जेब में सिर्फ 8 डॉलर (आज के समय के हिसाब से करीब 760 रुपये) होने का किस्सा काफी चर्चित है। आज वह फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स के चेयरमैन और सीईओ हैं। निवेश की लंबी अवधि वाली रणनीति के कारण प्रेम वत्स को कनाडा का वॉरेन बफे भी कहा जाता है।



प्रेम वत्स फिर से चर्चा में आ गए हैं क्योंकि सरकार ने उस विदेशी कंपनी के नाम पर मुहर लगा दी है जो देश के बड़े बैंकों में शामिल आईडीबीआई बैंक को खरीदेगी। कनाडा की इस कंपनी का नाम फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स है। यानी प्रेम वत्स की कंपनी की आईडीबीआई बैंक को करीब 53 हजार करोड़ रुपये में खरीद रही है।

प्रेम वत्स का जन्म 5 अगस्त 1950 को हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने 1971 में आइआइटी मद्रास से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद वह कनाडा चले गए और वेस्टर्न ओंटारियो यूनिवर्सिटी से एमबीए किया।

साल 1974 में उन्होंने कन्फेडरेशन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी शुरू की। यहां उन्होंने निवेश और शेयर बाजार की बारीकियां सीखीं। कुछ साल बाद उन्होंने अपनी निवेश कंपनी शुरू की और साल 1985 में फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स की स्थापना की।

कनाडा पहुंचे तो जेब में थे सिर्फ 8 डॉलर: प्रेम वत्स की जिंदगी का शुरुआती दौर आसान नहीं था। उनकी कहानी से जुड़ा एक चर्चित किस्सा है कि जब वह कनाडा पहुंचे, तो उनके पास सिर्फ 8 डॉलर थे। विदेश में नए सिरे से जिंदगी शुरू करना और अपने लिए करियर बनाना उनके सामने बड़ी चुनौती थी। हालांकि, उन्होंने मुश्किलों के सामने हार नहीं मानी।

क्यों कहते हैं कनाडा का वॉरेन बफे

प्रेम वत्स ऐसी कंपनियों में लंबे समय के लिए निवेश करने पर जोर देते हैं, जिनमें उन्हें भविष्य में बेहतर संभावनाएं दिखाई देती हैं। उनकी निवेश शैली अमेरिकी अरबपति वॉरेन बफे की वैल्यू इन्वेस्टिंग से मिलती-जुलती है। इसी वजह से उन्हें यह उपनाम मिला।

भारत में भी बड़ा निवेश

फेयरफैक्स का भारत से भी कारोबारी जुड़ाव है। कंपनी की भारतीय इकाई केरल के इस्क्रबैंक में बड़ी हिस्सेदारी रखती है। इसके अलावा ब्रुक्सरुकैपिटल और बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़े कारोबार में भी उसका निवेश है।

कितनी है प्रेम वत्स की नेटवर्थ

फोर्ब्स के अनुसार, प्रेम वत्स की संपत्ति करीब 2.6 अरब डॉलर आंकी गई है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 24800 करोड़ रुपये के बराबर बैठती है। हालांकि, अरबपतियों की संपत्ति शेयर बाजार और निवेशों के मूल्य में बदलाव के साथ घटती-बढ़ती रहती है। वह कनाडा के सबसे अमीर भारतीयों में शामिल हैं। उनकी उपलब्धियां सिर्फ व्यक्तिगत संपत्ति तक सीमित नहीं हैं। भारत और कनाडा के बीच कारोबारी संबंधों में भी उनका नाम महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है।

वृद्धि दरः भारत की जीडीपी कार्यप्रणाली को आईएमएफ का समर्थन, कहा- विकास का स्वागत

नई दिल्ली, एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने गुरुवार को भारत की अद्यतन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) गणना कार्यप्रणाली का समर्थन किया। आईएमएफ ने कहा कि यह कार्यप्रणाली सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के अनुरूप है। यह आईएमएफ की सलाह के पूरी तरह सुसंगत है।

आईएमएफ के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने बैंकॉक में पत्रकारों से कहा कि अद्यतन कार्यप्रणाली आईएमएफ के सांख्यिकी विभाग की सलाह से पूरी तरह मेल खाती है। श्रीनिवासन ने यह भी बताया कि भारत ने जीडीपी कार्यप्रणाली में संशोधनों को समझाने के लिए एक नोट जारी किया था। उन्होंने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के अच्छे काम को सराहा।

क्या आईएमएफ भारत की जीडीपी कार्यप्रणाली से सहमत है: आईएमएफ के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन ने स्पष्ट किया कि जीडीपी कार्यप्रणाली में संशोधन उनकी सलाह के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने जो किया है, वह अच्छी कार्यप्रणालियों के सुसंगत है। श्रीनिवासन ने सुधार की गुंजाइश स्वीकार की, लेकिन एमओएसपीआई के प्रयासों की सराहना की। आईएमएफ के सांख्यिकी विभाग ने भी इस कार्यप्रणाली को समर्थन दिया है।

ऊर्जा संकट और विनिमय दर पर भारत की प्रतिक्रिया कैसी रही: आईएमएफ के अधिकारी ने कहा कि भारत ने मजबूत बुनियादी सिद्धांतों के साथ ऊर्जा संकट का सामना किया। भारत ने इस संकट पर अच्छी प्रतिक्रिया दी है।

केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली पर मिलेगा डीए का तोहफा

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार है। उम्मीद थी कि 14 अक्टूबर 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है, लेकिन बैठक में इस पर कोई घोषणा नहीं हुई। ऐसे में अब कर्मचारियों की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी है। त्योहारी सीजन को देखते हुए कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार दिवाली से पहले डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। हालांकि, अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं, कैबिनेट ने इसी बैठक में एलिजिबल रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है। ऐसे में सवाल है कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले डीए बढ़ोतरी का तोहफा मिलेगा और महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है।

हम सबके ऊपर एक ईश्वर है, एक न एक दिन न्याय जरूर होगाः विजय माल्या

नई दिल्ली, एजेंसी। बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के फाउंडर और यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन विजय माल्या पर बैंकों के साथ हजारों करोड़ रुपये की हेराफेरी करने का आरोप है। हालांकि उनका दावा है कि बैंक उनसे बकाये से ज्यादा वसूली कर चुके हैं। उन्होंने बैंकों से बकाया लौटाने की मांग की थी। लेकिन एसबीआई की अगुवाई वाले बैंकों के ग्रुप ने हाल में बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया था कि अगस्त तक माल्या से लगभग 8,752 करोड़ रुपये वसूल किए जाने बाकी थे। इस बीच माल्या ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश भी लगाया है। माल्या ने कहा, कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्या मैं



अभी भी चोर या धोखेबाज हूं मैंने अपने ही पैसों से राजाओं जैसी शानदार जिंदगी जी और यही मेरा सबसे बड़ा अपराध बन गया। इसके लिए मुझे सजा दी जा रही है। हम सबके ऊपर एक ईश्वर है। एक न एक दिन न्याय जरूर होगा।

- **बैंकों का तर्क:** लंदन में रह रहे विजय माल्या ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर अपने खिलाफ आपराधिक मामलों को खारिज करने की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि बैंकों के साथ उनका विवाद सुलझ गया है क्योंकि बैंकों ने अपना पूरा बकाया वसूल कर लिया है। लेकिन एसबीआई की अगुवाई वाले बैंकों के ग्रुप ने हाल में बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया था कि अगस्त तक माल्या से लगभग 8,752 करोड़ रुपये वसूल किए जाने बाकी थे, जबकि डेट रिकवरी ऑफिसर अब तक 10,270 करोड़ रुपये वसूल कर चुके हैं। बैंकों ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस मामले में अटैच किए गए कुछ शेयर अभी भी सुरक्षित हैं और उन्हें बेचा नहीं गया है। बैंकों ने डीआर और अटैच की गई एसेट्स की बिक्री या वापसी के जरिए रिकवरी की कोशिश की है। इसी तरह ईडी और सीबीआई ने किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए लोन से जुड़े बैंक फ्रॉड, आपराधिक साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप वाले केस चलाए हैं।
- **भगोड़ा घोषित:** ईडी का कहना है कि रिकवरी से सिविल दावे तो निपट जाते हैं, लेकिन इससे पीएमएलए के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही अपने आप खत्म नहीं होती। माल्या ने तर्क दिया था कि कर्ज देने वालों की रिकवरी बकाये से ज्यादा है और इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही बंद की जाए। माल्या मार्च 2016 में विदेश भाग गए थे। सरकार ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया है।

मार्क जकरबर्ग ने आयरलैंड में की साल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डील



नई दिल्ली, एजेंसी। फेसबुक के फाउंडर और दुनिया के टॉप रईसों में शामिल मार्क जकरबर्ग ने आयरलैंड में इस साल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डील की है। जकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चान ने आयरलैंड के काउंटी वाटरफोर्ड में 16,000 वर्ग फुट के गोथिक-शैली वाले स्ट्रैंकली कैसल के लिए 57 मिलियन डॉलर का भुगतान किया है। यह इस साल आयरलैंड में किसी एक आवासीय संपत्ति के लिए चुकाई गई सबसे बड़ी कीमत है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक काउंटी वाटरफोर्ड के स्ट्रैंकली कैसल में स्थित स्ट्रैंकली कैसल की बिक्री 17 अगस्त को पूरी हुई। इस हवेली और इसकी 440 एकड़ की संपत्ति की अनुमानित कीमत 20 से 30 मिलियन यूरो बताई गई थी। लेकिन मार्क जकरबर्ग ने इससे कहीं ज्यादा कीमत चुकाई है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक जकरबर्ग की नेटवर्थ 261 अरब डॉलर है और वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं।

आयरलैंड में कारोबार

जकरबर्ग और उनकी पत्नी ने साथ ही तीन गेलिक एथलेटिक एसोसिएशन क्लबों को कुल 150,000 यूरो देने का वादा किया है। फेसबुक ने साल में 2009 आयरलैंड की राजधानी डबलिन में अपना अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय खोला था। मेटा के पास इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का भी मालिकाना हक है। कंपनी फिलहाल आयरलैंड में लगभग 1,500 लोगों को रोजगार देती है। जकरबर्ग ने 2004 में 19 साल की उम्र में फेसबुक की शुरुआत की थी।

प्रॉपर्टी की खासियत

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा से जुड़े कामकाज के सिलसिले में जब भी जुकरबर्ग और उनका परिवार आयरलैंड आएगा, तो यह प्रॉपर्टी उनके बेस के रूप में काम आएगी। 1830 में बने इस कैसल को आर्किटेक्ट जेम्स और जॉर्ज रिचर्ड पेन ने पूर्व कंजर्वेटिव सांसद जॉन केली के लिए डिजाइन किया था। तीन मंजिला यह हवेली लगभग 16,000 वर्ग फुट में फैली है और 440 एकड़ की एक विशाल जमीन पर स्थित है। बिक्री से पहले यह हवेली लंदन की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म आरएबी कैपिटल के को-फाउंडर माइकल एलेन बकले और उनकी पत्नी जियानकार्ला का था। जियानकार्ला के पिता दिवंगत होटल कारोबारी चार्ल्स फोर्टे थे। इस दंपति ने 25 साल पहले यह संपत्ति खरीदी थी और इस ऐतिहासिक इमारत का बड़े पैमाने पर रेस्टोरेशन कराया था। स्थानीय समुदाय ने जकरबर्ग परिवार का स्वागत किया है। उनका कहना है कि हाई-प्रोफाइल मालिकों के आने से इस क्षेत्र पर लोगों का ज्यादा ध्यान जाएगा।

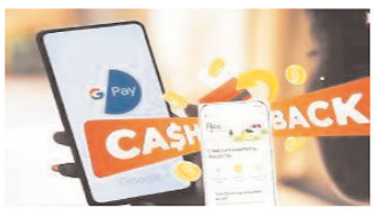
त्योहारी सीजन में गूगल पे का बड़ा तोहफा, ज्यादा कैशबैक के साथ मिलेंगे कई फायदे

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में नवरात्रे के साथ त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कई वित्तीय संस्था या बैंक के अलावा, यूपीआई के तहत अपनी सुविधा देने वाली कंपनियां ग्राहकों को एक से बढ़कर एक तोहफा देने में लगी हुई हैं। इस बीच गूगल पे ने अपने पात्र ग्राहकों के लिए तोहफा देते हुए खुशखबरी दी है।

हमारे सहयोगी टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, गूगल पे ने फ्लेक्स क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स को अपग्रेड किया है। गूगल ने अपने फ्लेक्स को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड (जिसे एक्सिस बैंक और एसबीआई कार्ड के साथ मिलकर पेश किया गया है) के गूगल पे रिवॉर्ड प्रोग्राम में बड़े बदलावों की घोषणा की है। इससे कई लोगों को फायदा होने वाला है। आइए इसके बारे में जानते हैं।

यूपीआई और हर रोज के खर्चों पर ज्यादा रिवॉर्ड: मिली जानकारी के मुताबिक, सबसे बड़ा यह बदलाव उन कार्डधारकों के लिए है जो यूपीआई और अन्य लेन-देन के जरिए रोज भुगतान या पेमेंट के लिए फ्लेक्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्लेक्स क्रेडिट कार्ड रखने वाले ग्रगल वन सदस्य, एक रिवॉर्ड साइकिल के दौरान कुल 15,000 रुपये से ज्यादा खर्च करने पर, अपने सभी खर्चों पर स्टार्स के रूप में 3.2 प्रतिशत वापस पा सकेंगे। यहां एक स्टार की कीमत 1 रुपये के बराबर है। जो लोग ग्रगल वन के सदस्य नहीं हैं, वे भी 15,000 रुपये की इसी सीमा को पार करने के बाद, अपने सभी योग्य खर्चों पर स्टार्स के रूप में 1.6 प्रतिशत वापस पा सकेंगे।

ये नए फायदे 16 अक्टूबर, 2026 से लागू होने जा रहे हैं। इस अपडेट किए गए प्रोग्राम के तहत, गूगल वन सब्सक्राइबर्स को रोजमर्रा के खर्चों पर कहीं ज्यादा रिवॉर्ड



मिलेंगे। वहीं, सभी फ्लेक्स कार्डहोल्डर्स को गूगल इकोसिस्टम के ज्यादा फायदों का एक्सेस मिलेगा, जिसमें गूगल वन एआई प्लान्स और चुनिंदा पिक्सेल व फिटबिट डिवाइस पर मिलने वाली छूट शामिल है।

इन लोगों के लिए अतिरिक्त बचत: गूगल, सदस्यों के लिए कैटेगरी-आधारित बोनस भी पेश कर रहा है। मतलब कि ग्रगल वन सदस्यों के लिए अतिरिक्त बचत और फायदे होने वाले हैं। पात्र यूजर्स को हर रिवॉर्ड साइकिल के दौरान प्रमुख फूड और ग्रोसरी ऐप्स पर किए गए 5,000 रुपये तक के खर्च पर 5 प्रतिशत का अतिरिक्त रिवॉर्ड मिलेगा। इसके अलावा, उन्हें यूटिलिटी बिल, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, मोबाइल रिचार्ज और ऐसी ही अन्य सेवाओं पर 3000 रुपये तक के खर्च पर 15 प्रतिशत का अतिरिक्त रिवॉर्ड मिलेगा।

बिक रहा आईडीबीआई बैंक, डील ऐलान के अगले दिन शेयर बेचकर भागे निवेशक

नई दिल्ली, एजेंसी। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स के आईडीबीआई बैंक में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 53,000 करोड़ रुपये (5.5 अरब डॉलर) में खरीदने के सौदे की घोषणा के अगले ही दिन इस शेयर को बेचने की होड़ सी मच गई। इस बैंक के शेयर में करीब 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। बीएसई पर आईडीबीआई बैंक का शेयर करीब 8 प्रतिशत टूटकर 83.33 रुपये पर आ गया। इससे पहले, बुधवार को सौदे की घोषणा से पहले आईडीबीआई बैंक के शेयरों में नौ प्रतिशत की तेजी आई थी, जिससे कंपनी के मार्केट कैपिटल में 8,086 करोड़ रुपये जुड़ गए थे। बता दें कि मार्च 2026 में यह शेयर 61.05 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। बता दें कि शेयर के 52 हफ्ते का हाई 118.45 रुपये है। जनवरी 2026 में शेयर इस स्तर तक गया था। इसके बाद से ही शेयर बिकवाली मोड में है। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स आईडीबीआई बैंक में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 53,000 करोड़ रुपये में खरीदेगी। यह किसी भारतीय बैंक में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने फेयरफैक्स की सब्सिडयरी कंपनी एम/एस 10955230 कनाडा इंक को रणनीतिक खरीदार के रूप में मंजूरी दी है। यह कंपनी सरकार की 30.48 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 26,620 करोड़ रुपये में और सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 26,440 करोड़ रुपये में खरीदेगी।

सरकार की कितनी है हिस्सेदारी: इस समय आईडीबीआई बैंक में संयुक्त रूप से सरकार और एलआईसी के पास 94.71 प्रतिशत हिस्सेदारी है। जून 2026 की होल्डिंग के अनुसार बैंक में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 45.48 प्रतिशत और एलआईसी की 49.24 प्रतिशत है। शेष 5.29 प्रतिशत शेयर सार्वजनिक और संस्थागत निवेशकों के पास हैं। एलआईसी भी एक सार्वजनिक बीमा कंपनी है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत है। बता दें कि आईडीबीआई की स्थापना औद्योगिक विकास वित्त संस्थान के रूप में हुई थी। लेकिन उसकी वित्तीय स्थिति खराब होने के बाद उसे सामान्य बैंक के रूप में पुनर्गठित किया गया था। आईडीबीआई बैंक इस समय रिजर्व बैंक के नियमों के तहत एक कॉमर्शियल बैंक के रूप में काम करता है।

एयरटेलः सैटेलाइट इंटरनेट की कतार में मस्क से काफी आगे हूं, तीन साल से ढांचा तैयार, सुनील भारती का बयान

नई दिल्ली, एजेंसी। स्टारलिंक को सैटेलाइट लाइसेंस मिलने में देरी संबंधी आरोपों पर भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने एलन मस्क पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने मस्क के एकाधिकार के दावों समेत सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा कि सैटेलाइट लाइसेंस मिलने की कतार में मैं मस्क से काफी आगे हूं लेकिन मैं भी अभी इंतजार ही कर रहा हूं। अगर मस्क से कुछ दिन पहले भी हमें मंजूरी मिल जाए तो हमें बेहद खुशी होगी। सुनील ने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनमी फोरम में यह बातें कहीं।

एलन मस्क सोशल मीडिया पर कर रहे शिकायत

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी अरबपति कारोबारी एलन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार शिकायत कर रहे थे कि भारत में उनकी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को फाइनल कमर्शियल मंजूरी मिलने में बहुत देरी हो रही है। मस्क ने परोक्ष रूप से आरोप लगाया था कि भारत के कुछ ताकतवर उद्योगपति (जैसे मुकेश अंबानी) अपना एकछत्र राज (मोनोपॉली) बनाए रखने के लिए राजनीतिक



प्रभाव का इस्तेमाल कर स्टारलिंक का रास्ता रोक रहे हैं। इस पर सुनील मित्तल से जब पूछा गया तो उन्होंने मस्क के दावों को नकारते हुए साफ किया कि देरी किसी भेदभाव के कारण नहीं, बल्कि भारत सरकार की सख्त सुरक्षा जांच और नियमों की वजह से हो रही है, जिसका सामना सभी को करना पड़ रहा है।

5 साल से चक्कर काट रहे भारती ग्रुप के सैटेलाइट

मित्तल ने याद दिलाया कि उनकी खुद की सैटेलाइट वेंचर यूटेलसैट वन वेब ने स्टारलिंक से पांच साल पहले ही आवेदन कर दिया था। ऐसे में अगर निष्पक्षता से देखा जाए, तो कतार में पहला हक उनका बनता है। मित्तल बोले, भारती ग्रुप के सैटेलाइट पिछले 5 वर्षों से भारत के ऊपर चक्कर काट रहे हैं और उनका ग्राउंड नेटवर्क भी पिछले 3 साल से पूरी तरह तैयार खड़ा है। इसके बावजूद नियमों के कारण उन्हें भी अभी तक फाइनल कमर्शियल रोलआउट की अनुमति नहीं मिली है। उधर, भारत सरकार पहले ही मस्क के आरोपों को पूरी तरह निराधार बता चुकी है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि स्टारलिंक, जियो और एयरटेल-समर्थित वनवेब तीनों ही इस समय रेगुलेटरी और नेशनल सिक्योरिटी क्लीयरेंस के एक ही चरण में हैं।

आकाश अंबानी ने कहा था, सभी को करना है नियमों का पालन

इससे पहले मस्क के आरोपों पर रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश अंबानी भी जवाब दे चुके हैं। उन्होंने कहा था, भारतीय टेलीकॉम कंपनियों पर मस्क का मोनोपॉली बनाने का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। जियो भी उसी भारतीय रेगुलेटरी सिस्टम के तहत काम कर रही है और नियमों का पालन कर रही है, जिसका पालन स्टारलिंक को करना है।

स्टेट प्रेस क्लब के आयोजन में गरबा प्रतिभागियों का सम्मान, अभिनव कला समाज में सजी सांस्कृतिक संध्या

शक्ति और भक्ति के रंग में रंगे कलमकार, गरबा-रास में झूमे पत्रकार

■ एक सत बुलेटिन, इंदौर

नवरात्रि के अवसर पर स्टेट प्रेस क्लब, मध्यप्रदेश की ओर से अभिनव कला समाज, गांधी हॉल में गरबा-रास निशा का आयोजन किया गया। पारंपरिक वेशभूषा, आरती और गरबा-रास की प्रस्तुतियों के बीच पत्रकारों और उनके परिवारों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। आयोजन में गरबा प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आरती के साथ हुआ। इसके बाद पारंपरिक परिधानों में सजे प्रतिभागियों ने गरबा और रास की प्रस्तुतियों से उत्सवी माहौल बनाया। आयोजन में अतिथि के रूप में श्रीमती स्वाति युवराज काशिद, पंडित सुनील मसूरकर, अधिवक्ता संजय चौहान, कमलकांत जैन, पंकज क्षीरसागर, शीतल राय और गायिका अन्नू शर्मा उपस्थित रहे।





गरबा-रास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्राची जैन, अर्चना सिसोदिया, अंजना यादव, प्रीति जैन, जया शेट्टी, प्रीति विश्वकर्मा, सुदिति राजपूत, आंचल रोकड़े, प्रियंका तिवारी, रश्मि रामचंदानी, प्रीति भारद्वाज, मधु वेद, मानवी राठौर, अंजली यादव, सुमित जैन, ऋषि यादव, पुष्कर सोनी, अजय भट्ट, जितेंद्र सिंह भाटिया, प्रकाश सुराणा, शैलेंद्र श्रीमाल, श्रीराम चौहान, नरेश गुप्ता और दीपक पाठक को पुरस्कृत किया गया।

स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य पत्रकारों और उनके परिवारों को सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से एक मंच पर लाना तथा भारतीय परंपराओं को प्रोत्साहित करना रहा। आयोजन के दौरान मेल-मिलाप और सांस्कृतिक सहभागिता का माहौल रहा। कार्यक्रम में प्रसादी के रूप में खिचड़ी, दूध, फलाहार और भोजन की व्यवस्था की गई।

न्यूज ब्रीफ

नवागत कलेक्टर आईएएस श्री पवन कुमार जैन ने किया पदभार ग्रहण



भिण्ड। नवागत कलेक्टर श्री पवन कुमार जैन ने आज कलेक्टर भिण्ड का पदभार ग्रहण कर लिया है।

कलेक्टर भिण्ड श्री पवन कुमार जैन (2013) बैंच के आईएएस अधिकारी हैं। श्री जैन उप सचिव, सहकारिता विभाग से स्थानांतरित होकर कलेक्टर भिण्ड बनाए गए हैं। कलेक्टर श्री जैन इसके पूर्व अपर कलेक्टर बैतूल, अपर आयुक्त (राजस्व) सागर संभाग, अपर कलेक्टर इंदौर के पद पर अपनी सेवाऐं दे चुके हैं।

जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक 17 अक्टूबर को

भिण्ड। महानवमी, दशहरा (विजयादशमी) एवं महर्षि बाल्मिकी जयंती तथा दीपावली के अवसर पर साम्प्रदायिक सौहार्द, सुरक्षा व्यवस्था एवं सतर्कता बरतने के संबंध में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक 17 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। अपर जिला दण्डाधिकारी ने अधीक्षण यंत्री एमपीईबी भिण्ड, अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग भिण्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड, कमाण्डेट होमगार्ड भिण्ड, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भिण्ड, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भिण्ड एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका भिण्ड को पत्र जारी कर नियत दिनांक एवं समय पर उक्त बैठक में उपस्थित होने को कहा है।

इंदौर में 28 अक्टूबर को अर्बन कॉन्क्लेव, ट्रीटेड वॉटर के दोबारा इस्तेमाल पर होगा फोकस

इंदौर। शहरों में पानी की बढ़ती मांग और प्राकृतिक जल स्रोतों पर दबाव कम करने के लिए उपचारित अपशिष्ट जल के दोबारा इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। इस उद्देश्य से 28 अक्टूबर को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में राज्य स्तरीय अर्बन कॉन्क्लेव-2026 आयोजित होगा। इसमें नगरीय विकास, जल संरक्षण, आधुनिक शहरी अधोसंरचना और निवेश की संभावनाओं पर विशेषज्ञों व नीति-निर्माताओं के बीच चर्चा होगी। कॉन्क्लेव में उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की रणनीति पर विशेष मंथन किया जाएगा। उद्योगों, निर्माण कार्यों, कृषि और उद्यानों की सिंचाई जैसी गैर-पेयजल जरूरतों में इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार होगा। इसका उद्देश्य ताजे पानी की खपत कम करना और जल संरक्षण को शहरी विकास की योजनाओं का अहम हिस्सा बनाना है। कार्यक्रम में भविष्य के शहरों की जरूरतों, डिजिटल गवर्नेंस, ग्रीन सिटी की अवधारणा और पर्यावरण-अनुकूल विकास पर भी चर्चा होगी। सुनियोजित नगरीय विकास, निवेश को प्रोत्साहन और आधुनिक शहरी सुविधाओं के विस्तार की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा।

जन विश्वास अभियान अंतर्गत ग्राम सढ़ा पहुंचे नवागत कलेक्टर और एसपी

स्कूल, आंगनवाड़ी और राशन दुकान का निरीक्षण कर ली जानकारी

■ एक सत बुलेटिन, भिण्ड

जन विश्वास अभियान के तहत नवागत कलेक्टर श्री पवन कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने शुक्रवार को विकासखंड मेहगांव के ग्राम सढ़ा और अड़ोखर का भ्रमण किया। उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा शासकीय संस्थाओं की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान शिक्षा, पोषण, राशन वितरण, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया।



स्कूलों में शिक्षण की जांच

कलेक्टर ने ग्राम सढ़ा स्थित शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यार्थियों व शिक्षकों की उपस्थिति, दर्ज संख्या तथा मध्याह्न भोजन की मीनू अनुसार व्यवस्था की जानकारी ली। बच्चों से संवाद कर उनका शैक्षणिक स्तर जाना गया। कलेक्टर ने बच्चों से पूछा कि वे पढ़-लिखकर क्या बनना चाहते हैं और शिक्षकों को बेहतर शिक्षा देने के निर्देश दिए। रसोई में तैयार मध्याह्न भोजन का अवलोकन कर उसकी गुणवत्ता भी देखी। आंगनवाड़ी और राशन दुकान का निरीक्षण कलेक्टर ने आंगनवाड़ी केंद्र मोहर सिंह का पुरा (सढ़ा) में दर्ज बच्चों की संख्या, उपस्थिति तथा बच्चों को दिए जाने वाले पौष्टिक आहार की जानकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका से ली। उन्होंने केंद्र की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। शासकीय उचित मूल्य की दुकान में हितग्राहियों की संख्या और वितरित हो रहे राशन की गुणवत्ता की जांच की। कलेक्टर ने सीईओ जनपद मेहगांव तथा ग्राम पंचायत सचिव को स्कूल व आंगनवाड़ी केंद्र के आसपास साफ-सफाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। आरोग्य केंद्र में सुविधाओं का जायजा ग्राम अड़ोखर में कलेक्टर ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टाफ की उपस्थिति और दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ली। केंद्र संचालक को ग्राम पंचायत सचिव से समन्वय स्थापित कर आरोग्य केंद्र के आसपास साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, पोषण, राशन, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार वर्मा, सीईओ जिला पंचायत श्री वीरसिंह चौहान, अपर कलेक्टर श्री राजन बी नाडिया, एसडीएम मेहगांव श्री नवनीत शर्मा, सीईओ जनपद मेहगांव श्री राजीव मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

माया देवी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. अनिल कुमार दीक्षित को संख्य योग फाउंडेशन ने सेवा एवार्ड 2026 प्रदान कर सम्मानित किया



■ एक सत बुलेटिन, देहरादून

संख्य योग फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. मुकुल शर्मा एवं अरिहंत हॉस्पिटल, देहरादून के डायरेक्ट डॉ.अभिषेक जैन ने सयुक्त रूप से माया देवी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. अनिल कुमार दीक्षित की 'स्पिरिट ऑफ़ सेवा एवार्ड 2026 प्रदान कर सम्मानित किया डॉ. अनिल कुमार दीक्षित के 125 शोधपत्र स्कोपस, एल्सवेयर जैसे अंतराष्ट्रीय डाटाबेस जर्नल में प्रकाशित हो चुके है उनके तीन पेटेंट भी ग्रांट हो चुके है ज्ञात हो कि कोरोना काल में रोग से बचाव हेतु सोशल-डिस्टेंसिंग के कामयाब फार्मूला साबित हुआ था इसे डॉ. दीक्षित ने ही 'दो गज़ क़ी दुरी छाते से होगी पूरी' का स्लोगन देकर पूरी दुनियां में कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ने का एक कारगर हथियार बना दिया था इस सम्मान पर डॉ.अनिल दीक्षित ने अपने छात्रों, शुभचिंतको, सहकर्मीगण, शिक्षकगण एवं परिवार का शुक्रिया अदा किया जिनकी वजह से उन्हें हमेशा सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहती है जो सेवाकार्य के लिये प्रेरित करती रहती है।

अंतर्विद्यालयीन भजन प्रतियोगिता सम्पन्न

इन्दौर। बाल निकेतन संघ पागनिसपागा में मोरेश्वर वामन मोघे की स्मृति में अंतर्विद्यालयीन सामूहिक भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें शहर के 21 विद्यालयों ने भाग लिया। डॉ. नीलिमा अदमणे, प्राचार्य संदीप धाकड़ ने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए पुरस्कार एवं स्मृति चिन्ह भेंट किए। प्रतियोगिता में न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल ने प्रथम, क्रिश्चियन एमिनेंट स्कूल ने द्वितीय और छत्रपति शिवाजी पब्लिक स्कूल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री के मुरैना आगमन पर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने किया आत्मीय स्वागत

■ एक सत बुलेटिन, मुरैना

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुरैना आगमन पर एसएएफ ग्राउंड स्थित हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर तथा पुष्पमालाओं से उनका आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर मौजूद थे। हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक विभिन्न स्थानों पर स्थानीय नागरिकों एवं विभिन्न संगठनों द्वारा पुष्पवर्षा कर मुख्यमंत्री डॉ. यादव का स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री एवं राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, सांसद शिवमंगल सिंह तोमर, विधायक श्रीमती सरला रावत, महापौर



श्रीमती शारदा सोलंकी मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल, मुख्यमंत्री के सचिव सुदाम खाड़े, चंबल संभाग के आयुक्त मनोज खत्री, कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़, पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा, जिला अध्यक्ष कमलेश कुशवाह सहित जिले के जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

डॉ. सलोनी सिडाना ने स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण किया, मरीजों से चर्चा कर लिया सेवाओं का फीडबैक

■ एक सत बुलेटिन, इंदौर

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश की मिशन संचालक डॉ. सलोनी सिडाना ने शुक्रवार को इंदौर जिले की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से चर्चा कर उपचार और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर फीडबैक लिया। निरीक्षण मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत किया गया। डॉ. सिडाना ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिचोली हप्सी, मुख्यमंत्री संजीवनी वार्ड-41, पटवारी प्रशिक्षण केंद्र और स्किल्स लैब का अवलोकन किया। इसके साथ ही निर्माणाधीन कैंसर चिकित्सालय में चल रहे कार्यों की स्थिति भी देखी। निरीक्षण के दौरान मिशन संचालक ने स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं, उपचार व्यवस्था और मरीजों को दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने भर्ती मरीजों से



बातचीत कर उनके उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं के अनुभव जाने। डॉ. सिडाना ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों के हितों को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। साथ ही संस्थाओं में जरूरी व्यवस्थाएं बेहतर बनाने और मरीजों को समय पर उचित उपचार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

नौ दिवसीय साधना पर्व में पुंसवन से विद्यारंभ और दीक्षा तक के संस्कार; यज्ञ, ध्यान और आरती में शामिल हो रहे श्रद्धालु

नवरात्रि में देवी आराधना के साथ जीवन संस्कारों का संदेश दे रहा गुरुधाम

■ एक सत बुलेटिन, इंदौर

कनाड़िया स्थित गायत्री शक्तिपीठ गुरुधाम में शारदीय नवरात्रि पर देवी आराधना के साथ जीवन के विभिन्न पड़ावों से जुड़े संस्कार भी कराए जा रहे हैं। नौ दिवसीय साधना पर्व में पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ और दीक्षा संस्कारों के आयोजन के माध्यम से भारतीय संस्कृति और परंपराओं में संस्कारों के महत्व को रेखांकित किया जा रहा है। गायत्री परिवार ट्रस्ट के संस्थापक प्रबंध ट्रस्टी शंकर लाल शर्मा, सुरेश बोरडिया और कमलेश्वर सिंह सिसोदिया ने बताया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार, शांतिकुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में आयोजित 54वें शारदीय नवरात्रि साधना पर्व की शुरुआत घट स्थापना, देवी पूजन और मंत्र जप के साथ हुई। पर्व के दौरान श्रद्धालु





नियमित साधना, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले रहे हैं। गुरुधाम में 12 अक्टूबर को पुंसवन, 13 अक्टूबर को नामकरण, 14 अक्टूबर को अन्नप्राशन और 15 अक्टूबर को मुंडन संस्कार आयोजित किए गए। 16 अक्टूबर को विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ, जबकि 17 अक्टूबर को दीक्षा तथा 18 अक्टूबर को जन्मदिवस और विवाहदिवस संस्कार आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को जीवन के विभिन्न चरणों में संस्कारों की भूमिका और उनके आध्यात्मिक महत्व से परिचित कराया जा रहा है। शक्तिपीठ में प्रतिदिन सुबह 7.30 बजे से पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ किया जा रहा है। शाम को नादयोग ध्यान साधना, चालीसा पाठ और आरती हो रही है। साधना पर्व के समापन पर पूर्णाहुति, गायत्री महायज्ञ, कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया जाएगा। ट्रस्ट पदाधिकारियों के अनुसार, नवरात्रि आत्मशुद्धि, आत्मोत्थान और आध्यात्मिक अनुशासन का अवसर है। साधना पर्व के माध्यम से श्रद्धालुओं को नियमित उपासना, संयमित जीवनशैली और सेवा भाव अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत जोन-12 के वार्ड-44 में जनकल्याण शिविर आयोजित

‘सबका साथ, सबका विकास’ के ध्येय से अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा योजनाओं का लाभ : सारंग

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**





खेल एवं युवा कल्याण तथा सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सहजता से पहुँचाने का सशक्त माध्यम है। अभियान के अंतर्गत नागरिकों की समस्याएँ सुनकर उनका समाधान किया जा रहा है और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। मंत्री श्री सारंग शुक्रवार को भोपाल के जोन क्रमांक-12, वार्ड क्रमांक-44 स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के अंतर्गत आयोजित जनकल्याण शिविर को संबोधित कर रहे थे। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने नागरिकों से आवेदन प्राप्त कर योजनाओं से संबंधित प्रकरणों और समस्याओं का निराकरण किया। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मूलमंत्र के अनुरूप समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर और महिला सशक्तिकरण की विभिन्न योजनाएँ नागरिकों को सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि शिविर में विभागीय अधिकारियों द्वारा पात्र नागरिकों के आवेदन भरवाकर उन्हें संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने की कार्यवाही की जा रही है। उनका निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनहितैषी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन समृद्ध मध्यप्रदेश और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का आधार है। शिविर में मंत्री श्री सारंग ने विभिन्न शासकीय योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति-पत्र एवं हितलाभ वितरित किए। इनमें पीएम स्वनिधि योजना, वृद्धावस्था पेंशन, कल्याणी पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन योजना के हितग्राही शामिल रहे। एडीएम श्री सुमित पांडे एवं श्री प्रकाश नायक ने शिविर में उपस्थित स्थानीय उद्यमियों और व्यापारियों से संवाद कर उनकी व्यापारिक एवं प्रशासनिक समस्याएँ सुनीं। अधिकारियों ने संबंधित समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। शिविर स्थल पर विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर नागरिकों को योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। प्राप्त आवेदनों में से मौके पर निराकरण योग्य प्रकरणों का समाधान किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना सुनिश्चित करें: सिंधिया

■ एक सत बुलेटिन, **अशोकनगर**



केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री सह स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जनकल्याण, जनसंवाद और क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, यह सुनिश्चित करना सभी जनप्रतिनिधियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि जनप्रतिनिधि निरंतर जनता के बीच रहें, उनकी समस्याओं को सुनें और उनके निराकरण के लिए प्रभावी प्रयास करें।

जनसंवाद के माध्यम से आमजन की आवश्यकताओं को समझकर ऐसे नवीन कार्यों और पहलों को आगे बढ़ाया जाए, जिनसे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी करने पर जोर देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुँचे। जनप्रतिनिधि योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुँचाने के साथ ही उनके प्रभावी क्रियान्वयन में भी सक्रिय भूमिका निभाएँ। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अशोकनगर में जारी विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी साझा की।

साथ ही, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत किए जा रहे विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों के संबंध में भी चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि जनसेवा के संकल्प के साथ निरंतर कार्य करते हुए क्षेत्र के विकास को गति देना, जनसमस्याओं का समाधान करना और शासन की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुँचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

सरकारी कामकाज में सरल हिंदी के प्रयोग और युवा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



मेरा युवा भारत, मध्यप्रदेश, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय राजभाषा हिंदी कार्यशाला एवं विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रभावी प्रयोग, राजभाषा नियमों के पालन तथा हिंदी के प्रचार-प्रसार पर विचार-विमर्श किया गया। वहीं, समीक्षा बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित युवा कार्यक्रमों की प्रगति और आगामी कार्ययोजनाओं पर चर्चा हुई। कार्यशाला में डॉ. जवाहर कर्नावट, सलाहकार, प्रवासी भारतीय साहित्य एवं संस्कृति शोध केंद्र, रवींद्रनाथ टैगोर भोपाल तथा निदेशक, अंतरराष्ट्रीय हिंदी केंद्र और श्री अरविंद श्रीधर, निदेशक, माधवराव सप्रे संग्रहालय संस्थान ने सहभागिता की। वक्ताओं ने हिंदी की प्रासंगिकता, जनसामान्य से उसके जुड़ाव और सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रभावी उपयोग के महत्व पर अपने विचार रखे। अधिकारियों को कार्यालयीन पत्राचार एवं दैनिक कार्यों में सरल और सहज हिंदी का अधिकाधिक उपयोग करने तथा राजभाषा नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान हिंदी के तकनीकी प्रयोग, यूनिकोड के माध्यम से हिंदी में कार्य करने की सुविधा और भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान की भावना पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यशाला के पश्चात मेरा युवा भारत, मध्यप्रदेश के अधिकारियों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य निदेशक श्री मंगल जाखड़ ने की, जबकि संयोजन श्री सागर वाधवानी ने किया। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित युवा कार्यक्रमों, विभागीय गतिविधियों की प्रगति, निर्धारित लक्ष्यों और आगामी कार्ययोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में कार्यक्रमों का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने तथा युवा कार्यक्रमों में युवाओं की अधिकाधिक सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया गया।

महालक्ष्मी नगर सब स्टेशन में 50 एमवीए का पॉवर ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत

भोपाल। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि दशहरा और दीपावली पर्व के दौरान बिजली की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने इंदौर के 132 केवी जीआईएस महालक्ष्मी नगर सब स्टेशन में 50 एमवीए क्षमता का अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापित कर ऊर्जीकृत किया है। इससे सब स्टेशन की क्षमता बढ़कर 100 एमवीए हो गई है। इस वृद्धि से संबंधित क्षेत्रों में बढ़ते विद्युत भार को संभालने और पारेषण व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने में मदद मिलेगी। इससे महालक्ष्मी नगर सब स्टेशन से जुड़े व्यावसायिक एवं घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।जीआईएस महालक्ष्मी नगर सब स्टेशन से 33 केवी के 7 फीडरों के माध्यम से पश्चिमी इंदौर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगभग 90 हजार उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की जाती है।

खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में सेवा संकल्प के अंतर्गत रक्तदान शिविर आयोजित

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



पं.खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान चिकित्सालय, भोपाल में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में महाविद्यालय के स्नातक वं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के कुल 37 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इसके अतिरिक्त, संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी स्वैच्छिक रक्तदान कर सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्त संग्रह की व्यवस्था के लिए हमीदिया अस्पताल, भोपाल की रक्त संग्रह टीम अपनी विशेष रक्तदान बस के साथ संस्थान पहुँची। शिविर का मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित करना था। शिविर की विशेष उपलब्धि यह रही कि रक्तदाताओं में ओ-नेगेटिव एवं एबी-नेगेटिव जैसे दुर्लभ रक्त समूह भी पाए गए। इससे आपातकालीन परिस्थितियों में दुर्लभ रक्त समूहों की उपलब्धता और स्वैच्छिक रक्तदान के महत्व को रेखांकित किया गया। शिविर में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप नाश्ते की व्यवस्था भी की गई। शिविर के सफल आयोजन में रोग निदान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. रीता सिंह, डॉ. भारती ददलानी एवं डॉ. संगीता उइके तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. बसंती गुरु ने विशेष तकनीकी सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. उमेश शुक्ला, अस्पताल अधीक्षक डॉ. हरिप्रकाश शर्मा, डॉ. आर. के. पति, राष्ट्रीय सेवा योजना एवं रेड रिबन क्लब के प्रभारी डॉ. मनोज रावत तथा सेवा संकल्प अभियान के नोडल अधिकारी डॉ. पवन किरार ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। इसके साथ ही हमीदिया अस्पताल के ब्लड बैंक से डॉ. श्वेता एवं जे.पी. अस्पताल के रेड रिबन क्लब से श्रीमती अंतिशा दुबे ने भी आयोजन में उल्लेखनीय योगदान दिया। इस आयोजन ने समाज सेवा, मानवीय संवेदना एवं जनकल्याण के प्रति संस्थान के विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों की प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से प्रदर्शित किया।

शारदीय नवरात्र मेला: मैहर और विंध्याचल में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेल प्रबंध



भोपाल। शारदीय नवरात्र मेला 2026 के दौरान मैहर एवं विंध्याचल में दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत भोपाल मंडल होकर गुजरने वाली 14 जोड़ी ट्रेनों को मैहर स्टेशन पर 5 मिनट तथा 06 जोड़ी ट्रेनों को विंध्याचल स्टेशन पर 2 मिनट का अस्थायी ठहराव प्रदान किया गया है। मैहर स्टेशन पर यह व्यवस्था 11 से 22 अक्टूबर 2026 तक, जबकि विंध्याचल स्टेशन पर 11 से 26 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। मैहर स्टेशन पर 14 जोड़ी ट्रेनों का 5 मिनट का अस्थायी ठहराव नवरात्र मेला अवधि में मैहर स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए निम्नलिखित ट्रेनों को अस्थायी ठहराव दिया गया है। रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि यात्रा प्रारंभ करने से पहले संबंधित ट्रेन के ठहराव, समय एवं परिचालन संबंधी नवीनतम जानकारी की पुष्टि अवश्य कर लें। ट्रेन संबंधी जानकारी रेलवे की अधिकृत पूछताछ सेवा एनटीईएस, रेल मदद अथवा हेल्पलाइन नंबर 139 से प्राप्त की जा सकती है।

लोको रखरखाव में नवाचार: इटारसी में शून्य खर्च पर टेस्टिंग यूनिट विकसित की गई

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



पश्चिम मध्य रेल द्वारा रेल इंजनों के रखरखाव को अधिक प्रभावी, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में नवाचारपूर्ण पहल की गई है। इसके अंतर्गत इटारसी स्थित विद्युत लोको शेड में पुराने उपकरणों से प्राप्त पुर्जों का उपयोग कर बिना किसी अतिरिक्त खर्च के पोर्टेबल टेस्टिंग यूनिट विकसित की गई है। वहीं, तुगलकाबाद स्थित विद्युत लोको शेड में डैम्पर की जांच के लिए आधुनिक, धूल-मुक्त एवं ध्वनि-रोधी केबिन तैयार किया गया है। इन पहलों से रखरखाव कार्यों में दक्षता बढ़ाने, संसाधनों का बेहतर उपयोग करने तथा कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इटारसी स्थित विद्युत लोको शेड की इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के कर्मचारियों ने उपलब्ध पुराने पुर्जों का पुनः उपयोग करते हुए पोर्टेबल पावर थाइरिस्टर टेस्टिंग यूनिट विकसित की है। इस यूनिट की सहायता से बीएचईएल निर्मित ऑक्जिलरी कन्वर्टर में लगे चार थाइरिस्टरों की अलग-अलग जांच कर खराब पुर्जे की पहचान की जा सकती है। इस नवाचार से विद्युत उपकरणों में खराबी की पहचान करने और मरम्मत में लगने वाले समय को कम करने में सहायता मिलेगी। साथ ही, बिना अतिरिक्त वित्तीय व्यय के उपयोगी जांच उपकरण विकसित करना रेलवे के उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग और कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तुगलकाबाद स्थित विद्युत लोको शेड में डैम्पर की जांच के लिए पारदर्शी कांच की दीवारों वाला विशेष केबिन बनाया गया है। डैम्पर रेल इंजन में झटकों को नियंत्रित करने और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नरवाई प्रबंधन की वैज्ञानिक तकनीकों से किसानों को कराया अवगत

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

किसानों को नरवाई प्रबंधन की वैज्ञानिक एवं आधुनिक तकनीकों से अवगत कराने के उद्देश्य से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, जिला भोपाल द्वारा आदमपुर छावनी प्राथमिक साख सहकारी संस्था में कार्यशाला आयोजित की गई। परियोजना संचालक, आत्मा (ञ्झ्र) एवं उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में कृषि अधिकारियों, कर्मचारियों और किसानों को फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन तथा नरवाई जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। कार्यशाला में कृषि वैज्ञानिकों, सहायक संचालक कृषि अभियांत्रिकी, रिलायंस सीबीजी प्लांट के निदेशक सहित कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और विभिन्न क्षेत्रों से आए किसान शामिल हुए। विशेषज्ञों ने बताया कि नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरता एवं मृदा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। साथ ही, इससे वायु प्रदूषण बढ़ने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। विशेषज्ञों ने किसानों को नरवाई जलाने के स्थान पर फसल अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाने, जैविक पदार्थ के रूप में उपयोग करने तथा अन्य वैकल्पिक तरीकों से उनका सदुपयोग करने की जानकारी दी। रिलायंस सीबीजी प्लांट के निदेशक ने फसल अवशेषों से कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के उत्पादन की संभावनाओं और इसकी उपयोगिता के बारे में बताया। किसानों को नरवाई प्रबंधन की वैज्ञानिक तकनीकों के प्रति जागरूक करें।

मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत शिविर आयोजित

संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा हुए शामिल, जनसमस्याओं का हुआ त्वरित निराकरण

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत शिविर शुक्रवार को भोपाल संभाग के राजगढ़ ज़िले की नगर परिषद तलेन में आयोजित किया गया। शिविर में विधायक नरसिंहगढ़ श्री मोहन शर्मा, संभागायुक्त भोपाल श्री कर्मवीर शर्मा, नरसिंहगढ़ विधायक श्री मोहन शर्मा, कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री अमित तोलानी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. इच्छित गढ़पाले की उपस्थिति में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों का निराकरण किया गया. इस दौरान अधिकारियों ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के संबंध में आवेदको से वन-टू-वन चर्चा भी की। आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उनकी समस्याओं एवं शिकायतों को सुना गया तथा संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर उनके निराकरण की कार्रवाई की गई। विधायक नरसिंहगढ़ श्री शर्मा ने ग्रामीणों से आपसी सहमति से विवाद सुलझाने, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने एवं जैविक खेती अपनाने की अपील की विधायक नरसिंहगढ़ श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्र?येक शुक्रवार को तलेन तहसील में जनसमस्याओं के निराकरण के लिए जनविश्वास अभियान के अंतर्गत शिविर का आयोजन होना सौभाग्य की बात है। आज भोपाल संभागायुक्त श्री कर्मवीर शर्मा सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी यहां उपस्थित हैं, जो आमजन की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण सुनिश्चित करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा अनेक समस्याओं का समाधान किया जाता है, वहीं कुछ समस्याओं का निराकरण हम आपसी समन्वय और समझदारी से भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी बातों को लेकर विवादों में उलझने के बजाय आपसी सहमति से समस्याओं का समाधान करना चाहिए। विशेषकर जमीन संबंधी विवादों में अनावश्यक उलझने से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार किसान थोड़े से क्रोध में आकर अपनी मेहनत की कमाई न्यायालयीन प्रकरणों में खर्च कर देते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य संवारने के लिए उन्हें शिक्षा से जोड़ना आवश्यक है। विधायक नरसिंहगढ़ श्री शर्मा ने बिजली की बचत करने की अपील करते हुए कहा कि विद्युत उत्पादन में संसाधनों का उपयोग होता है, इसलिए बिजली का अनावश्यक उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा आमजन को रोजगार उपलब्ध कराने तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों से रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग से बचने तथा जैविक खेती को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है और इसके दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ सकते हैं। किसान गोबर की खाद एवं जैविक खाद का उपयोग कर मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखें।

स्वामी एक सत प्रयास जनकल्याण समिति के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **अमित शर्मा** द्वारा प्रकाशन स्थल बी-9 विवेक विहार कॉलोनी, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.) पिन-474001 से प्रकाशित एवं सर्वोदय ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, नया बाजार केनरा बैंक के पास ग्वालियर (म.प्र.)-474001 से मुद्रित। स्थानीय संपादक राजीव शुक्ल* पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।
RNI - MPHIN/2019/79098/ E-mail: EKSATBULLETIN@GMAIL.COM, WWW.EKSATBULLETIN.IN, मार्केटिंग एवं अन्य जानकारी हेतु हेड ऑफिस संपर्क करें- ए-1 माचना कॉलोनी, शा.राजीव गांधी हाई स्कूल शिवाजी नगर 6 नंबर बस स्टाप पास भोपाल। फोन: 0755-4515227, मोबाइल: 9691653088